



FROM DEMOLITION TO DEVELOPMENT



Plan Rental Options for Housing Poor, Says NSDF

ALTHOUGH countries across the world – including India – have signed international resolutions to stop forced evictions, demolitions continue in cities worldwide.

In December 2004 in Mumbai, the Maharashtra State Government undertook a massive demolition drive, targeting all those slum dwellers who had come to the city after 1995. An estimated 60,000 houses were demolished, leaving hundreds of thousands homeless.

The demolitions continued for two months, and had considerable support from the middle class. Finally, in mid February, 2005, the Chief Minister relented. He promised housing to all those slum dwellers who could prove that they had come to the city before 2000. >



एन.एस.डी.एफ.: “गरीबों के लिये किराये के विकल्प सोचो”

हालांकि भारत सहित संसार भर के राष्ट्र जबरन बेदखली को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय संकल्प पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, संसार के अनेक शहरों में डेमोलिशन जारी हैं।

दिसम्बर 2004 में मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने विशाल स्तर पर डेमोलिशन शुरू किये। उनका निशाना थे वे सब झोंपड़पट्टीवासी जो शहर में 1995 के बाद आये थे। अनुमानित रूप से 60000 घर तोड़ दिये गये और हजारों-लाखों लोग बेघर हो गये।

डेमोलिशन दो दिन चले और मध्यम वर्ग की ओर से इन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। अंततः, मध्य फरवरी 2005 में मुख्य मंत्री नरम पड़े। साथ ही, उन्होंने वादा किया कि जो झोंपड़पट्टीवासी यह सिद्ध कर सकता है की वह 2000 के पहले मुंबई आया था, उसे घर दिया जायेगा। >

INSIDE / आवास

1 FROM DEMOLITION TO DEVELOPMENT

- * Plan Rental Options for Poor
- * Hollow Excuses Against Housing Poor
- * गरीबों के लिये किराये के विकल्प सोचो
- * गरीबों के आवास के विरुद्ध खोखले बहाने

6 MAKING CONNECTIONS: The World/India

- * WUF: SDI Calls for People-Centred Development
- * Police Panchayats Multiply
- * More Strength to Regional Feds.
- * डब्ल्यू.यू.एफ.:एस.डी.आई. ने जन केंद्रित विकास मांगा
- * पुलिस पंचायतें बढ़ीं
- * प्रादेशिक संगठनों को अधिक ताकत



14 MONEY-MATTERS

- * MM Rings in MicroCredit Year
- * Banks & Poor Jointly Explore Housing Finance
- * म.मि. ने शुरू किया माइक्रो क्रेडिट वर्ष
- * बैंकों और गरीबों ने मिल कर विचारा आवासीय वित्त



20 RESETTLE, REHAB

- * Great North Mumbai Shift Begins
- * महान उत्तरी मुंबई प्रयाण शुरू



25 TALKING OF TOILETS

- * Towards Zero Open Defecation
- * Tirupur Toilets are Turning Point
- * The Case of the Unbuilt Toilet
- * खुले में शून्य मल की ओर
- * तिरुपुर शौचालय महत्वपूर्ण मोड़ हैं
- * 'शौचालय जो बन नहीं सका' की कहानी



35 HOUSING

- * Dharavi: Slum Development Without Slum Dwellers!
- * 'Showlapur' Shows the Way
- * धारावी: झोंपड़पट्टीवासियों के बिना झोंपड़पट्टी विकास
- * शोलापुर ने रास्ता दिखाया



41 TAKING CHARGE

- * All India Slum Dwellers Debate Loan Interest
- * Rise of Community Contractors
- * New Leaders Emerge in Smaller Feds
- * अखिल भारतीय झोंपड़पट्टीवासियों की ऋण के ब्याज पर बहस
- * समुदाय ठेकेदारों का उदय
- * छोटे संगठनों में नये नेता उभरे





> Even as the demolitions gathered strength across the city, Magsaysay Award winner and President of the National Slum Dwellers Federation, Jockin Arputham was awarded his second international honour: the French 'National Order of Merit' for helping the underprivileged.

In an interview thereafter with Jyoti Punwani of *Times of India*, Jockin suggested that the poor, whose services are vital to running the city, be given a fair chance rather than be driven away inhumanly from their homes.

Q: Are the large-scale demolitions making people go back to their villages?

A. JOCKIN: This time, the BMC has demolished in one month what would normally take seven months. These demolitions have been more mechanised, more ruthless and more inhuman. They have exposed the politicians' tall talk. Had the MLAs and MPs wanted, they could have stopped them in a day; instead, they went into hiding.

Where are the human rights groups, those who talk about the girl child? Babies are dying of pneumonia in the open. If one girl is raped, notices are issued to the authorities. Who knows how many girls sleeping on the roads were raped?

No one will go back. I'm willing to give Mumbai's middle class a plane ticket to go back to their villages. They have acres to go back to. Will they?

The authorities say these slums came up after 1995, hence they are illegal. Everyday, hundreds of ads ask professionals, managers, to come and work in Mumbai. You don't have place for more people, but do you stop them? No. And not a single advert says: Bring proof of residence before 1.1.95!

On the one side you are opening up doors. Middle-class people come here, find a house. The poor also come here to work. They can't afford a house, so they squat wherever they can and become a visible presence. Therefore you break their homes, ruin their livelihood and drive them out inhumanly.

Q: Do you see a solution?

AJ: Why don't you create an alternative for the poor? Why should they not have the same chances for employment as the middle class? The custodians of the city should create a sites and services zone on the city's periphery. Put up 10x10 rooms, common toilets and taps, and ask the poor to pay five rupees everyday. Make NGOs responsible for collection...Give us a chance, let us enumerate the slums, categorise the residents, and find a place for all.



Q: The Corporation says you don't pay taxes, you are a burden on the infrastructure?

AJ: Do you know that everyday, a poor family staying on the footpath pays Rs 35 just for water? Where's the free stay? We don't travel free, there are no free ration shops for us. We pay for everything from our pockets. Yet, you look upon us as *chors* and pickpockets.

What about the industrialists who bribe BMC officers to allow them to encroach on public space? Today, all the land in the city is habitable. We made it so. We were squatting there, that's how these places got to be known. We are in fact human earthmovers and tractors – we levelled the land first.

We contribute. We carry your shit out of the city. I don't see citizens' groups dredging sewers and digging roads. This city is not for the rich only. We need each other. I don't beg, I wash your clothes. Women can go to work because we are there to look after their children. The staff in Mantralaya, the Collectorate, the Bombay Municipal Corporation, even the police live in slums. Because we are there, women can walk safely at night.

People talk about making Mumbai a world-class city. How can it be world-class without a place for its poor? It's my dream that one day, all slum-dwellers will refuse to go to work. Will Mumbai survive? Who will build your grand projects and work in your malls? You want us to be your coolies, you want all our services – but you don't want us to live here?"

In State demolitions people's belongings are forcibly destroyed or stolen....

राजकीय डेमॉलिशन में लोगों का सामान जबरन नष्ट या चोरी कर लिया जाता है.....





> जब की शहर में डेमोलिशन जोर पकड़ रहे थे, मैगसेसे पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय झोंपड़पट्टीवासी संगठन के अध्यक्ष, जोकिन अरपुथम को अत्याधिकारियों की सहायता करने के लिये एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, फ्रांस का 'नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट'। इस के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की ज्योति पुनवानी से बातचीत में जोकिन ने सुझाव दिया कि गरीबों को, जिनकी सेवा शहर के लिये अत्यावश्यक है, एक निष्पक्ष मौका मिलना चाहिये, न कि उन्हें अपने घरों से अमानवीय तरीके से भगाना चाहिये।

प्रश्न : इतने बड़े पैमाने पर डेमोलिशन के कारण क्या लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं?

अ. जोकिन : इस बार, मु.न.पा. ने एक महीने में जो डेमोलिशन किये हैं साधारणतया वो सात महीनों में होते हैं। ये डेमोलिशन ज्यादा मशीनी, ज्यादा बेदर्द और ज्यादा अमानवीय थे। इन्होंने राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातों का पर्दाफाश किया है। यदि एम.एल.ए. और एम.पी. चाहते, तो एक दिन में इन्हें रोक सकते थे, लेकिन वो सब छुप गये। कहां हैं मानव अधिकार गुट, वो जो बालिकाओं की बात करते हैं? खुले में पड़े बच्चे निमोनिया से मर रहे हैं : यदि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो प्राधिकरण को नोटिस जारी किये जाते हैं, कौन जाने सड़कों पर कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ?

कोई वापस नहीं जायेगा, मैं मुंबई के मध्यम वर्ग को अपने गांव वापस जाने के लिये हवाई जहाज के टिकट देने के लिये तैयार हूँ। उन के पास वापस जाने के लिये जमीनें हैं। जायेंगे क्या? प्राधिकरण का कहना है कि ये झोंपड़पट्टियां 1995 के बाद बनीं इसलिये अवैध हैं। हर दिन सैकड़ों विज्ञापन व्यवसायिकों और मैनेजर्स को मुंबई आ कर काम करने के लिये बुलाते हैं। तुम्हारे पास लोगों के लिये जगह नहीं है पर क्या उन्हें रोकते हो? नहीं। और एक भी विज्ञापन नहीं कहता कि 1.1.95 के पहले के घर का प्रूफ लाना! एक ओर से तो तुम दरवाजा खोलते हो। मध्यम वर्गीय लोग यहां आते हैं और घर ढूँढ लेते हैं। गरीब भी यहां काम के लिये आते हैं। वो घर नहीं ले सकते, इसलिये जहां जगह मिली बैठ जाते हैं और नजरों में खटकते हैं। इसलिये आप उनके घर तोड़ते हो। उनकी जीविका बरबाद करते हो और अमानवीय तरीकों से भगा देते हो।

प्रश्न : क्या आपको समाधान नजर आता है?

अ ज : आप गरीब के लिये विकल्प क्यों नहीं बनाते? उन्हें मध्यम वर्ग के जैसे ही नौकरी के अवसर क्यों नहीं मिलते? नगर के अभिभावकों को शहर की सीमाओं पर स्थल एवं सेवा क्षेत्र बनाने चाहियें 10 बाई 10 के कमरे बनाओ, साझा संडास और नल हों और गरीब को हर दिन पांच रुपये देने को कहो। इसे वसूलने की जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों को दो। हमें अवसर दो, हमें झोंपड़पट्टियों की गणना करने दो, रहवासियों के वर्ग बनाने दो और सबके लिये जगह ढूँढने दो।

प्रश्न : पालिका का कहना है कि आप लोग टैक्स नहीं देते, आप संरचना पर बोझ हैं?

अ ज : तुम्हें पता है कि फुटपाथ पर रहने वाला एक गरीब परिवार सिर्फ पानी के लिये रोज रु.35 देता है? मुफ्त में कहां रहा? हम मुफ्त में यात्रा नहीं करते, हमारे लिये कोई मुफ्त राशन की दुकान नहीं है। हम हर चीज के लिये अपनी जेब से पैसे देते हैं, फिर भी आप लोग हमें चोर और जेब कतरे समझते हैं।

उन उद्योगपतियों का क्या जो मु.न.पा. अफसरों को रिश्त देते हैं जिससे की सार्वजनिक जगहें दबा सकें? आज शहर की सारी जमीन रहने लायक है। हम ने उसे ऐसा बनाया है। हम वहां बैठे थे, इसलिये उन जगहों की पहचान बनी। हम तो मानवीय भूसंचालक और टैक्टर हैं।

हमने पहले जमीन समतल की। यह हमारा योगदान है। हम आपका मैला शहर के बाहर ले जाते हैं। मुझे कोई नागरी गुट सीवर लाइन साफ करते या सड़कें खोदते नहीं दिखते। यह शहर सिर्फ अमीरों के लिये नहीं है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। मैं भीख नहीं मांगता। मैं आपके कपडे धोता हूँ। औरतें काम पर जाती हैं क्यों कि हम आप के बच्चों की देखभाल करते हैं। मंत्रालय के, कलेक्टर के, मुंबई नगरपालिका के कर्मचारी, और पुलिसवाले भी झोंपड़पट्टियों में रहते हैं। हमारे कारण, महिलायें रात को सुरक्षित घूमती हैं। लोग मुंबई को विश्वस्तर का शहर बनाने की बात करते हैं। अपने गरीबों को जगह दिये बिना यह विश्व-स्तर का कैसे हो सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन, सारे झोंपड़पट्टीवासी काम पर जाने से मना कर देंगे। क्या मुंबई जीवित रह पायेगी? कौन आपकी भव्य योजनायें बनायेगा और दुकानों में काम करेगा? आप चाहते हो कि हम आप के कुली बने रहें? आप हमारी सारी सेवार्यें चाहते हो – पर यह नहीं चाहते की हम यहां रहें?



.... in a joint exercise with the State, people dismantle their own houses prior to relocation.

.....राज्य के साथ मिल कर किये गये कार्यक्रम में, पुनर्वसन के पहले लोग अपने घर स्वयं तोड़ देते हैं।



Facts Don't Support 'No Land' Excuse for Housing Poor, says SPARC

SIXTY PER CENT of Mumbai's population lives in slums on about 13% of the land area. This statistic reveals starkly the inequality of land use in the city and its failure to make available land that can be used for affordable housing for the poor.

In Mumbai, the oft-repeated excuse is that there is no land. SPARC's stand is that this excuse is hollow. The reality is, with real estate prices amongst the highest in the world, the sale and allotment of public land to commercial interests is lucrative. The reclamation of the land at Nariman Point several decades ago was an early example of collusion that lined the pockets of both builders and politicians.

One Chief Minister dereserved hundreds of plots meant for public purposes to benefit the builder lobby but a Public Interest Litigation did not allow his gameplan to succeed. Another allowed a few hundred acres of No Development land to be opened up for exploitation.

A private business group owns more than 400 hectares. Salt pan lands are available and if the Government wanted, sizable chunks of textile mill lands can be made available for housing the poor.

Land is available in Mumbai but for whom and at what price? Not for the poor, it seems.

'People Come to City for Earning, not Housing'

Governments seem to believe that if they do something to help the urban poor, it will encourage migration – whereas demolitions will serve as a stop signal to future immigrants.

The money spent on demolition drives is wasteful because it does not achieve its objective. Demolitions, besides, destroy the asset base of the poor, the modest houses they have incrementally built up over time.

The fact is people come to the city to earn a living, not to get housing. Those whose homes are demolished by the State have not and will not return to village India. They will move to other areas in the city, pursuing their right to a livelihood, building up from scratch.

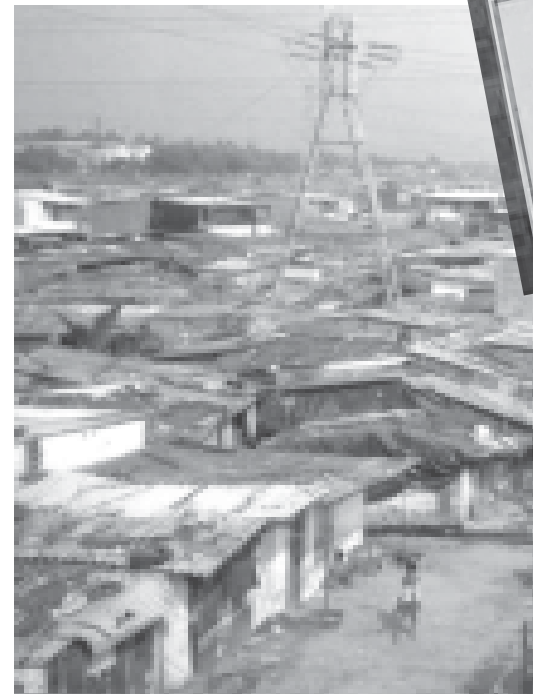
बिना तथ्यों के सहारे है गरीब आवास का बहाना 'जमीन नहीं है' कहता है स्पार्क

मुंबई की साठ प्रतिशत आबादी लगभग 13 प्रतिशत जमीन पर झोपडपट्टियां बना कर रहती है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि नगर के जमीन उपयोग में कितनी असमता है और वह कितनी असफल है। जहां गरीब के लिये घर बन सकें, ऐसी जमीन उपलब्ध कराने में मुंबई में हमेशा

बहाना होता है। पर यह एक खोखला बहाना है। वास्तविकता यह है कि यहां जमीन की कीमतें विश्व की अधिकतम कीमतों में से हैं और सार्वजनिक जमीन का व्यवसायिक आवंटन और खरीद फरोख्त लाभकारी है। दसियों साल पहले हुआ नरीमन पॉइंट का रिकलेमेशन ऐसी सांठ-गांठ का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिससे बिल्डरों और राजनेताओं दोनों की ही जेबें गरम हुई थीं।

एक मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक भूमि के सैंकड़ों टुकड़ों का आरक्षण रद्द कर दिया जिससे बिल्डर लाभ उठा सकें। लेकिन जनहित याचिका ने इस युक्ती को सफल नहीं होने दिया। दूसरे ने अविकासशील जमीनों में से कुछ सैंकड़ों एकड़ जमीन संदोहन के लिये खोल दी।

एक निजी व्यवसायिक ग्रुप 400 हेक्टेअर जमीन का मालिक है। साल्ट पैन जमीन मुहैया है और यदि सरकार चाहे तो कपड़ा मिलों की जमीनों के काफी टुकड़े गरीबों के आवास के लिये उपलब्ध कराये जा सकते हैं। मुंबई में जमीन है, पर किसके लिये और किस कीमत पर? कम से कम गरीब के लिये तो नहीं!



ABOUT US

The Alliance of SPARC, National Slum Dwellers Federation (NSDF), and Mahila Milan



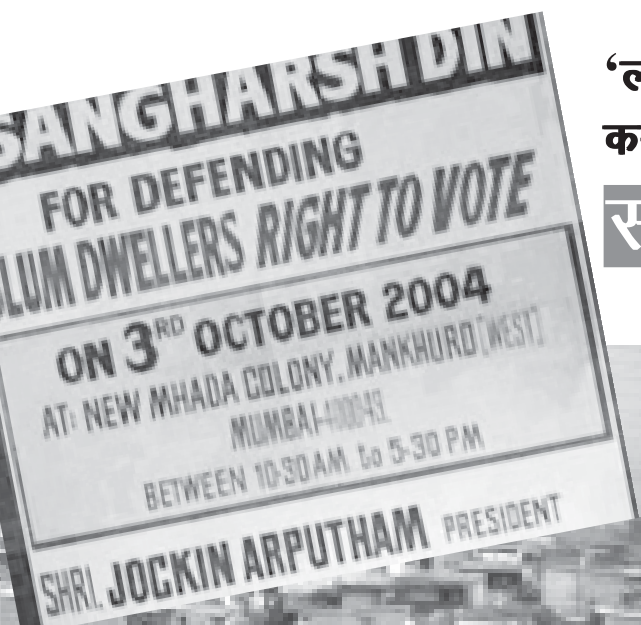
सब संभव है
(Everything is Possible)

THE Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC) is one of the largest Indian NGOs working on housing and infrastructure issues for the urban poor. Working with pavement-dwellers in Byculla since 1984, SPARC tied up with the National Slum Dwellers Federation in 1986. Together, they formed another community-based organization, the Mahila Milan. This Alliance of three works in over 50 cities in India and networks with about 15 countries internationally.

The National Slum Dwellers Federation (NSDF), founded in the mid-1970s, is a grassroots movement which seeks to mobilise the urban poor to come together, articulate their concerns, and find solutions to the problems they face. Today, the NSDF works with about half a million households in 52 cities across the country.

Mahila Milan, meaning 'Women Together' in Hindi, is a decentralised network of poor women's collectives that manage credit and savings activities in their communities. Mahila Milan was founded in recognition of the enormous potential that women's groups have in transforming relations within society and in improving the lives of the poor. Today, Mahila Milans collect savings from and give out loans to thousands of women across the country.

SPARC Samudaya Nirman Sahayak, or Nirman (SSNS) for short, is a section 25 not-for-profit company founded in 1998 to take on construction projects in partnership with poor communities. It undertakes projects recommended by the Alliance. The rationale for creating this separate entity is that construction requires distinct specialisations, legal and institutional arrangements.



‘लोग शहर में आते हैं कमाने, घर के लिये नहीं!’

सरकारों को लगता है कि यदि वे शहरी गरीबों के लिये कुछ करेंगे तो इससे स्थानान्तरण को बढ़ावा मिलेगा – जब कि डेमोलिशन भविष्य के प्रवासियों को रुकने का इशारा करेंगे।

डेमोलिशन पर खर्च किया गया पैसा बेकार है क्योंकि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके अलावा डेमोलिशन गरीबों की संपत्ति नष्ट कर देता है।

तथ्य यह है कि लोग शहर में जीविका कमाने आते हैं, घर के लिये नहीं। जिनके घर राज्य द्वारा नष्ट कर दिये गये हैं वे ग्रामीण भारत न तो गये हैं न ही जायेंगे। वे एक नयी शुरुआत कर के, जीविका की खोज में शहर के किसी दूसरे इलाके में चले जायेंगे।

— झॉपड़पट्टी डेमोलिशन पर शीला पटेल और सुंदर बुरा द्वारा लिखे गये लेख से —

PIL Denying Voting Rights to Slum Dwellers Dismissed

SEVERAL NGOs (including SPARC) and NSDF intervened when a Public Interest Litigation (PIL) petition was filed in August 2004 in the Bombay High Court challenging inclusion of slum and pavement dwellers' names in the Electoral Roll.

At the September hearing, the Chief Justice gave interveners time to file affidavits before he decided whether or not to admit the case.

The PIL petitioners contended that people who had encroached on lands to house themselves could not be considered "ordinary residents" of those lands, as was required under the People's Representation Act of 1950. While the interveners claimed this was a flawed interpretation of the Act.

Though the Court later dismissed the petition, the case is indicative of the deep divide between the poor and the rest of the city which seeks to deny the poor even this basic legal right.

The PIL was a key theme discussed at NSDF's Annual Meet. See Pg. 41

जनहित याचिका, एन.एस.डी.एफ. के वार्षिक अधिवेशन में चर्चित मुख्य विषय था। देखें पृष्ठ 41

झोपड़पट्टीवासीयों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की जन हित याचिका खारिज

स्पार्क सहित कई गैर सरकारी संगठनों, और एन.एस.डी.एफ. ने अगस्त 2004 में मुंबई उच्च न्यायालय में झॉपड़पट्टी एवं फुटपाथवासियों के नाम निर्वाचक सूची में होने के विरुद्ध दायर की गयी जनहित याचिका में हस्तक्षेप किया है। सितम्बर की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने केस लेने या न लेने के पक्ष में निर्णय लेने के पहले मध्यस्थकर्ताओं को हलफनामे दाखिल करने का समय दिया।

याचिका दायर करने वालों ने दावा किया है कि घरों के लिये जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को उस जगह का "साधारण रिहायशी" नहीं माना जा सकता, जो की 1950 के पीपल्स रेपेरेजेंटेशन एक्ट के तहत अपेक्षित है। दूसरी ओर मध्यस्थकर्ता कहते हैं कि यह एक्ट की गलत व्याख्या है।

हालांकि यह याचिका अभी तक न्यायालय में स्वीकृत नहीं हुई है यह केस गरीब और बाकी शहर के बीच की खाई दर्शाता है जिसके रहते गरीब को इस वैधानिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है।

सो सायटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऐरिया रिसोर्स सेंटर्स (स्पार्क) शहरी गरीबों के लिये आवास और संसाधन के क्षेत्र में काम कर रही भारत की एक बड़ी गैर सरकारी संस्था है। 1986 में फुटपाथवासियों के साथ काम शुरू करने वाले स्पार्क ने 1986 में राष्ट्रीय झॉपड़पट्टी फेडरेशन और महिला मिलन, दो समुदाय संस्थाओं के साथ नाता जोड़ा। यह गठबंधन आज देश के 50 से अधिक शहरों में काम करता है और विदेश में लगभग 15 देशों में नेटवर्किंग करता है।

राष्ट्रीय झॉपड़पट्टी फेडरेशन (एन.एस.डी.एफ.) 70 के दशक में स्थापित हुई। यह एक जमीनी आंदोलन है जो शहरी गरीबों को अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिये और उनका समाधान ढूँढने के लिये तैयार करते हैं। आज एन.एस.डी.एफ. देश के लगभग 5 लाख परिवारों के साथ काम करती है।

महिला मिलन, गरीब महिलाओं के समूहों का विकेंद्रित तंत्र है। महिलायें अपने समुदायों में बचत और ऋण की गतिविधियां चलाती हैं। महिला मिलन की स्थापना यह मान कर हुई की महिला समूह समाज के आंतरिक रिश्ते बदलने की जबरदस्त क्षमता रखता रखते हैं जिससे गरीब की जिंदगी सुधर सकती है। आज महिला मिलन ने देश भर में गरीब महिलाओं को हजारों ऋण दिये हैं और करोड़ों रुपयों की बचत इकट्ठी की है।

स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक, या निर्माण, (एस.एस.एन.एस.), 1998 में स्थापित की गयी सेक्शन 25 गैर लाभकारी कम्पनी है जो गरीब समुदायों के साथ भागीदारी में निर्माण परियोजनाएँ करेगी। यह गठबंधन द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएँ करती है। इस अलग संस्था बनाने का औचित्य यह है की निर्माण के काम में स्पष्ट विशिष्टताएँ, वैधानिक एवं संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

हमारे बारे में
स्पार्क, राष्ट्रीय
झॉपड़पट्टी फेडरेशन
एवं महिला मिलन का
गठबंधन



सब संभव है
(Everything is
Possible)



World Urban Forum, Barcelona Only People-Centred Development Can Help Poor, says SDI

IN AN eloquent appeal at the opening plenary session of the 2004 World Urban Forum in Barcelona in September, SDI and NSDF President Jockin Arputham asked international agencies and donors to help support a people-centred and community-driven approach to development. If the poor are left out of the development process, he stated baldly, then that would be the end of it.

Everyone spoke of building people's capacities – but instead, the capacity of the poor was being taken away by local bodies and development agencies who hardly bothered to involve communities of the urban poor in their work.

The Global Campaign for Secure Tenure had been held in many countries. But had anything happened on the ground? How many donors had kept money aside separately to finance housing? On the one hand, there was talk of stopping demolitions – on the other, countries which had pledged to fulfill Millennium Development Goals (MDG) continued to demolish slums.

“The phrase ‘cities without slums’” Jockin pointed out sardonically, “is being interpreted by some to mean slums should be removed and slum dwellers sent far away from the city!”

Slum/Shack Dwellers International (SDI) sought to change things on the ground, not waste effort on rhetoric. Federations of the urban poor were managing savings, organising women, and delivering development to the poor.

“As President, I am proud that through the network of SDI, more than 200,000 households round the world have got secure tenure. We have built more than 50,000 homes in South Africa alone and 10,000 toilet seats for residents of Mumbai slums. In Cambodia, the Prime Minister has promised to upgrade 100 slums every year along with tenure. This is the manner in which SDI federations work – in close collaboration with local bodies and governments.

“We do not come before you with a begging bowl,” he declared, “but to invite you to join us in this journey. We feel this work can be multiplied several times over if it is supported by UN HABITAT and other agencies. We urge that

the donors present here together create a Fund to promote a development approach which is people-centred and community-driven. UN HABITAT in turn can facilitate this approach with central and local governments.

“And since it is our belief,” said Jockin firmly, “that governments alone cannot

tackle the problems of the urban poor, we propose that communities of the urban poor from all over the globe come together at the next World Urban Forum and suggest how we can go forward. May I request your support in this endeavour?”



At Barcelona WUF, L to R, Jockin Arputham, A. S. Garud, Chief Engineer, Indian Railways (Mumbai), and Dr. S. V. Joshi, Metropolitan Commissioner, MMRDA.

बारसीलोना डबल्यू.यू.एफ. में, दायें से बायें, जोकिन अरपुथम, ए.एस. गरुड़, मुख्य अभियंता, भारतीय रेलवे (मुंबई), एवं डा.एस.वी. जोशी, मेट्रोपॉलिटन आयुक्त, एम.एम.आर.डी.ए.।

2004 विश्व नागरी गोष्ठी, बारसीलोना

एस.डी.आई: “केवल जन केंद्रित विकास ही गरीब की मदद कर सकता है”

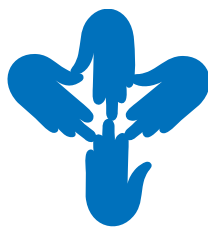
बारसीलोना में हुई 2004 की विश्व नागरी गोष्ठी के प्रारंभिक पूर्ण सत्र में एस.डी.आई एवं एन.एस.डी.एफ. के अध्यक्ष जोकिन अरपुथम ने भावपूर्ण आग्रह किया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें और दाता, विकास के लिये जन केंद्रित और समुदाय चलित तरीकों का समर्थन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विकास प्रक्रिया में से गरीब को छोड़ दिया जाये, तो आगे कुछ बचेगा ही नहीं।

सभी ने लोगों की क्षमताएँ बढ़ाने की बातें कीं – लेकिन, गरीब की क्षमताएँ तो स्थानीय निकाय और विकास संस्थाएँ कम करती जा रही हैं क्यों कि अपने काम में वे शहरी गरीब समुदायों को साथ में लेती ही नहीं हैं।

सुरक्षित भूमि अधिकार के लिये विश्व अभियान कई राष्ट्रों में किया गया है। पर क्या जमीनी स्तर पर कुछ हुआ ? कितने दाताओं ने आवासीय वित्त के लिये पैसा अलग से रखा? एक ओर तो डेमोलिशन रोकने की बात थी – दूसरी ओर ऐसे देश भी थे जिन्होंने मिलेनियम विकास लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया था, फिर भी झोंपड़पट्टियों का डिमोलिशन जारी किये हुए थे। जोकिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, ‘कुछ नगरपालिकाएँ “बिना झोंपड़पट्टियों के शहर” का अर्थ निकाल रही हैं की झोंपड़पट्टियाँ हटा कर झोंपड़पट्टीवासीयों को शहर से दूर भेज देना चाहिये।’

–बातचीत और बहस में समय गवाने की जगह – स्लम/शैक डवैलर्स इंटरनेशनल –एस.डी.आई ने जमीनी हालात में बदलाव लाने का प्रयास किया। शहरी गरीबों के संगठन बचत संचालन कर रहे हैं, महिलाओं को संगठित कर रहे हैं और गरीब तक विकास पहुँचा रहे हैं।

“अध्यक्ष के तौर पर, मैं गर्व से कहता हूँ की एस.डी.आई. के तंत्र द्वारा, संसार भर में 200,000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित भूमि अधिकार मिले हैं। हम ने दक्षिण अफ्रीका मात्र ही में 50000 से अधिक घरों का निर्माण किया है और मुंबई के झोंपड़पट्टीवासियों के लिये 10,000 शौचालय सीट बनायी हैं। कंबोडिया के प्रधान मंत्री ने वादा किया है कि वे हर वर्ष 100 झोंपड़पट्टियों को सुरक्षित अधिकार दे कर उनका सुधारण करेंगे। यह एस.डी.आई संगठन का काम करने का तरीका है – स्थानीय निगमों और सरकारों के नजदीकी सहयोग से।



**MAKING CONNECTIONS:
The World**

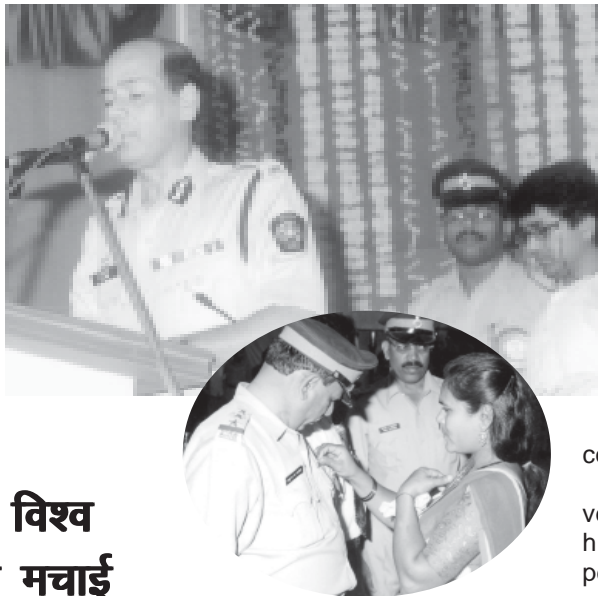


“हम आप के सामने मांगने नहीं आये” उन्होंने कहा, ‘पर हम अपनी यात्रा पर आप को आमंत्रित करते हैं। हमें लगता है कि यदि हैबिटेट और अन्य संस्थाएँ इसे समर्थन दें तो यह काम कई गुणा बढ़ाया जा सकता है। हम उपस्थित दाताओं से आग्रह करते हैं कि वे मिल कर ऐसी निधि बनायें जो जन-केंद्रित और समुदाय-चलित विकास के तरीकों को प्रोत्साहित करे। साथ ही हैबिटेट इस तरीके को केंद्र एवं स्थानीय सरकारों के साथ मिल कर सहजता से करे।

“और क्यों कि हमें विश्वास है,” जोकिन ने दृढ़ता से कहा, “की शहरी गरीबों की समस्याओं का सामना सरकारें अकेली नहीं कर सकतीं, हमारा प्रस्ताव है कि संसार भर के शहरी गरीबों के समुदाय अगली विश्व नागरी गोष्ठी में आयें और सुझाव दें कि आगे कैसे जा सकते हैं। क्या मैं इस प्रयास के लिये आपके समर्थन की विनती कर सकता हूँ?”

‘His idea is a hit. UN invites A.N. Roy to Barcelona’ wrote the *Indian Express*, Sept. 2004, referring to the innovative Police Sahayak scheme introduced in 2003 in Pune.

‘उनका विचार हिट हुआ। यू.एन. ने ए.एन.रॉय को बारसीलोना आमंत्रित किया’ सितम्बर 2004 में *इंडियन एक्सप्रेस* ने पुणे में 2003 में शुरू की गयी नवीन पुलिस सहायक योजना के संदर्भ में लिखा।



पुणे पुलिस सहायकों ने विश्व नागरी गोष्ठी में हलचल मचाई

नवीन झोंपड़पट्टी पुलिस सहायक योजना, जिसमें झोंपड़पट्टीवासी और पुलिसवाले मिल कर शहर की झोंपड़पट्टियों में शांति बनाये रखते हैं, सिर्फ पुणे से मुंबई तक ही सफलतापूर्वक नहीं आयी, इसने बारसीलोना में सितम्बर 2004 में हुई विश्व नागरी गोष्ठी में भी हलचल मचा दी।

मुंबई से आया स्पर्क—एन.एस.डी.एफ.—महिला मिलन गठबंधन एक मात्र ऐसा दल था जिसमें उनके पुलिस आयुक्त साथ थे। और जब मुंबई जैसे महानगर के पुलिस आयुक्त बोलते हैं तो सभी ध्यान लगाकर सुनते हैं।

बारसीलोना के अपने प्रस्तुतिकरण में आयुक्त ए.एन. रॉय ने बताया की कैसे पुणे और मुंबई दोनों जगह — झोंपड़पट्टी की ओर से सात महिलाओं व तीन पुरुषों की एक कमेटी, एक निर्धारित पुलिस अफसर के साथ निकटता के साथ काम करती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव झोंपड़पट्टी समुदाय इस उद्देश्य से करता है कि समुदायों के आपसी झगड़े उनके स्तर पर ही निपटा दिया जायें।

सामुदायिक हस्तक्षेप छोटे छोटे झगड़ों को हाथ से निकलने नहीं देता — जैसे की पानी की लाइन में खड़े लोगों में झगड़ा या शराब पीकर घर में मार पीट करना — रॉय ने इस ओर ध्यान दिलाया की औपचारिक वैधानिक तंत्र में जाने की जगह इस तरह से झगड़े सलताने में कितने समय और साधनों की बचत होती है। उनका कहना था की झोंपड़पट्टी पुलिस योजना, गरीबों और पुलिस के पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन ला रही है। पहले गरीबों को पुलिस पर विश्वास नहीं था और पुलिस अधिकतर झोंपड़पट्टियों को अपराध का प्रजनन स्थान मानती थी। लेकिन, साथ में काम कर के और साथ में समय बिताने के बाद दोनों ही ओर के दृष्टिकोण बदल रहे हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि लोगों की भागीदारी के कारण, झोंपड़पट्टियों में सुरक्षा की प्रवर्तक यह युक्ति बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है, वह भी सरकार से आसानी से नहीं मिलने वाले अतिरिक्त साधन मांगे बिना।

उनके जोरदार भाषण ने सुनने वालों को बहुत जोश दिलाया। विश्व नागरी गोष्ठी में आये एस. डी.आई. के प्रतिनिधि अपने शहरों में आवास से पहले इस प्रकार की समुदाय योजनायें बनाने की इच्छा ले कर वापिस गये।

Pune Police Sahayaks Make Ripples at WUF

THE innovative Zopadpatti Police Sahayak Scheme, in which slum-dwellers and police jointly maintain the peace in city slums, has not only travelled successfully from Pune to Mumbai, it created a stir at the 2004 World Urban Forum at Barcelona in September.

The SPARC-NSDF-Mahila Milan Alliance from Mumbai was the only group there that had its Police Commissioner on its team! And when the Police Commissioner of a metropolis like Mumbai talks, everyone sits up and listens.

In his presentation at Barcelona, Commissioner A.N. Roy explained how — in both Pune and Mumbai — a seven women-three men committee in a slum worked in close coordination with a designated police official. These representatives were selected by the slum community with the aim to resolve disputes at the community level itself.

Community intervention could prevent minor wrangles from going out of hand (such as petty quarrels among people standing in a queue for water, or alcoholism leading to domestic violence). Roy drew attention to the time and energy saved by such dispute resolution without resorting to the formal legal system.

The slum policing scheme, he said, transformed the traditional relationship between the poor and the police, in which the poor distrusted the police and the police, more often than not, looked upon slums as breeding grounds for crime. But, by working together and spending time together, both sets of perceptions

were changing.

Another key advantage was that this strategy of promoting safety within slums could be implemented on a large scale because of people’s participation and without soliciting additional resources from the government, which were not easily available.

His stirring talk fired the listeners’ imagination. SDI delegates to WUF went away with intent to go beyond housing and experiment with similar community policing schemes in their cities.



**MAKING CONNECTIONS:
The World**



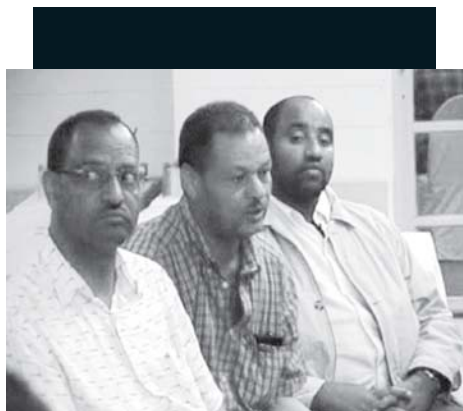
Ethiopians Explore Slum Upgrading in Mumbai

"It's a tough task I have before me," grinned Joel Bodnick, Shack Dwellers International Coordinator, "I have to explain SDI – a network which supports mainly poor women in poor countries – to a government audience which is all male!"

He was speaking of a group of Ethiopian City Managers (like Municipal Commissioners here) and officials of the Ministry of Federal Affairs come to study community-led slum upgradation in Mumbai. One of their key projects is the Kebele housing redevelopment project in Addis Ababa, which emphasizes community based approaches in slum reconstruction, relocation and upgrading.

In earlier discussions at the '04 SDI meet in Manori, it was pointed out that SDI could play a crucial role in Ethiopian cities in strengthening voices against a purely privatization model which pushes poor people away from their *idirs* (slums) in the city centre towards its margins.

The visitors from Ethiopia were overwhelmed with the size and complexity of Mumbai and felt more comfortable in Pune, where they observed the working of the sanitation partnership with the city. The NGO-CBO partnership driving developments was new and unusual for them and they wondered how it could be reproduced in Ethiopia.



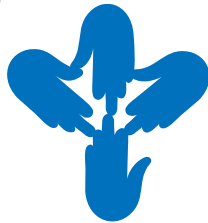
Ethiopian city managers came to Mumbai to study slum upgradation schemes.

इथियोपिआई शहरी मैनेजर झोंपड़पट्टी सुधारन योजनायें देखने मुंबई आये

इथियोपिआई मुंबई झोंपड़पट्टी सुधारन देखने आये

"मेरे सामने बड़ा ही कठिन काम है" शैक डवैलर्स इंटरनैशनल के समन्वयकर्ता जोएल बोलनिक हंसे। 'मुझे एस.डी.आई के बारे में बताना है जो की एक ऐसा तंत्र है जो गरीब देशों में अधिकतर गरीब महिलाओं को सहारा देता है और सुनने वाले हैं सरकारी अफसर जो सब मर्द हैं।"

वो बात कर रहे थे इथियोपियन नगर मैनेजरों के ग्रुप के बारे में (जैसे हमारे नगरपालिका आयुक्त) जो फंडरल मामले के मंत्रालय के अफसरों के साथ मुंबई में समुदाय संचालित झोंपड़पट्टी



MAKING CONNECTIONS:
The World

सुधारन का अध्ययन करने आये थे। उनकी एक मुख्य परियोजना है ऐडिस अबाबा स्थित केबेले आवास पुनर्विकास योजना जो झोंपड़पट्टी पुनर्निर्माण, पुनर्वसन और सुधारन के समुदाय आधारित तरीके पर जोर देती है। उनकी यात्रा में यू.एन. हैबीटैट ने मदद की थी। 2004 में मनोरी में हुई एस.डी.आई मीटिंग में हुई बातचीत में यह बताया गया था की उन आवाजों का समर्थन करने में एस.डी.आई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो शुद्धतया निजीकरण मॉडल के विरुद्ध हैं, जिससे गरीबों को शहर के केंद्र में बसे उनके इदिरों (झोंपड़पट्टीयों) से शहर के किनारे पर धक्का दे दिया जाता है।

इथियोपिया के हमारे अतिथि मुंबई की विशालता और जटिलता से अभिभूत हो गये थे और पुणे में अधिक आराम से रहे। वे पुणे शहर के साथ शौचालय साझेदारी देखने गये थे। काम को गति देने वाली एन.जी.ओ-सी.बी.ओ साझेदारी उनके लिये नयी और असाधारण थी और उन्होंने सोचा कि उसे किस प्रकार इथियोपिया में शुरू किया जा सकता है।



A 21-people delegation from Alliance partner CODI (Community Organisation Development Institute), Thailand, visited Mumbai and Pune in April '04. Pune's Mahila Milan used the opportunity to organise a large housing exhibition and invite lots of city slum dwellers too, to learn about affordable housing and relocation projects. After an earlier exchange such as this, the Thais adapted MM's design for their own housing projects.

गठबंधन भागीदार सी.ओ.डी.आई (कम्युनिटी औरगनाइजेशन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट), थाइलैंड की ओर से 21 सदस्यों का दल अप्रैल 04 में मुंबई और पुणे आया। इस मौके पर पुणे की महिला मिलन ने एक बड़ी आवास प्रदर्शनी का आयोजन किया और शहर के झोंपड़पट्टीवासियों को आमंत्रित किया कि वे कम कीमत की आवास और पुनर्वसन योजनाओं के बारे में जान सकें। ऐसे ही एक आदान प्रदान के बाद थाई लोगों ने अपनी आवास योजनाओं के लिये महिला मिलन का डिजाइन अपनाया था।

एन.एस.डी.एफ ने सूनामी के बाद पुनर्वास में सहायता की

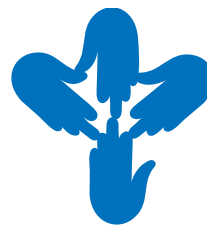
अक्टूबर में हुए एन.एस.डी.एफ. के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद करइकल झोंपड़पट्टीवासी संगठन बहुत उत्साहित था। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई गहरी बातचीत के बाद शहर में पहला सामुदायिक शौचालय बनाने की मंजूरी मिल गयी थी, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि किस झोंपड़पट्टी में संकुल का निर्माण करेंगे और जमीन भी ले ली थी लेकिन 26 दिसंबर 2004 को उनकी आशाएँ और उनके घर, सभी सूनामी का पानी बहा कर ले गया। पौंडीचेरी झोंपड़पट्टीवासी संगठन के नेतृत्व में कई शहरों के नेताओं के दल ने, जिस में मुंबई के पद्मा भी थे, पौंडीचेरी, नागपट्टिनम और करइकल के प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन और पानी की तुरंत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराने के अलावा संगठन ने 10 अस्थायी घर, तीन बालवाड़ियाँ, तीन कुएँ और चार शौचालयों का भी निर्माण किया। फरवरी 2005 में उन्होंने तीन क्षेत्र चुने जहाँ नहीं के बराबर सहायता पहुंची थी और लगभग 30 स्थायी घरों का निर्माण शुरू किया है।



Federation leaders surveyed tsunami-affected areas in the south.

फेडरेशन के नेताओं ने दक्षिण के सूनामी प्रभावित इलाकों का दौरा किया

भारतीय संगठन सूनामी की तबाही से निपटने में श्रीलंका के गंतबंधन की भी सहायता कर रहा है। जनवरी और फरवरी में गंतबंधन के दल, जिनमें तीन प्रतिनिधि उड़ीसा के थे, जहाँ समुद्री चक्रवात आते रहते हैं, श्रीलंका गये जिससे कि वे पुनर्वसन का संचालन करने की स्थानीय क्षमताओं का जायजा ले सकें और उन्हें सूनामी के बाद आवास युक्तियाँ बनाने में सहायता कर सकें। श्रीलंका वालों को स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने में और संगठन द्वारा बनाये गये आवास कार्यक्रम कार्यान्वित करने में बढ़ावा मिला। स्पार्क की सिलीन डिक्रुज़ ने अपनी पहली यात्रा के बाद लिखा—इस तरह की रिपोर्ट में जमीनी स्तर पर अनुभव की गयी सभी भावनाएँ लिखना कठिन है। समुद्र में लहरे ऐसी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जब कि सभी उसे शक की नजरों से देखते हैं। एक ओर जहाँ बहुत उदासी है, वहीं पुनर्निर्माण की आशा भी है और लोगों के भाव और उर्जा फिर से स्फूर्त हो रहे हैं। अब डर है चोरों का जो बचा खुचा भी लूट लेना चाहते हैं। पुरुष और महिलायें मलबे में गहने और कागजात ढूँढते हैं पर बेकार में। अब दूसरा डर है, अपने घर खो कर बेदखल होने का। यदि संभाल कर काम नहीं किया गया तो दूसरी सूनामी हो सकती है।



**MAKING CONNECTIONS:
The World**



Temporary toilets put up by PSDF-Alliance for tsunami victims

सूनामी पीड़ितों के लिये पी.एस.डी.एफ.—गंतबंधन द्वारा बनाये गये अस्थाई शौचालय

PSDF Aids Post-Tsunami Rehousing

THE Karaikal Slum Dwellers Federation was very excited because after intense negotiations, the national leadership had given the go ahead for the first community toilet in town. They had identified the slum and secured the land where they were going to build this block. On 26th December, 2004, however their hopes – along with their homes – were washed away by the tsunami.

Led by the Pondicherry Slum Dweller's Federation, a team of leaders from six cities (including Padma from Mumbai) surveyed affected areas in Pondicherry, Nagapattinam and Karaikal. Besides immediate assistance in the form of food, clothing, utensils and water, the Federation built 90 temporary houses, three *balwadis*, three wells and four toilets. In February 2005, they targeted three areas – where little relief had reached – to begin construction of about 80 permanent houses.

In January and February, Alliance teams went to Sri Lanka to help build local capacities to manage the rehabilitation, and plan a post-tsunami housing strategy. The Sri Lankans were encouraged to open up dialogue with local authorities to implement federation designed and run housing programmes.

Wrote SPARC's Celine D'Cruz, after her first visit, "It is difficult to capture all the emotions that you sense on the ground in a report like this. The sea rolls on as if nothing happened while all around look at it with suspicion. While there is a lot of sadness, there is also hope for reconstruction and people's spirits and energies are just picking up.

"The fear now is of thieves who come to plunder whatever is left. Men and women search through the wreckage for their jewellery and documents but in vain. The other fear is of losing their homes and of evictions. If not managed with care, this can cause a second tsunami."



And Now 200 Slums Have Police Sahayaks

LESS than a year since the scheme was launched (June 04), Mumbai's toted up an impressive score of 200 slum-police panchayats.

The Police Sahayak Scheme was inaugurated in Mumbai nine months after Pune. The slum-police panchayat, made up of 10 police *sahayaks* or helpers from the slum (seven women, three men) and a local police officer, is a joint exercise to maintain local peace. For instance, police committees have brought pressure to shut down the 'shops' of locals who illegally brew and sell alcohol - thus bringing down the incidence of drunkenness-related violence. Meanwhile, the local Mahila Milan assists the illegal brewers to develop new livelihoods. Without community volunteers, the police would find it impossible to control conflicts of this kind.

Expanding Horizons

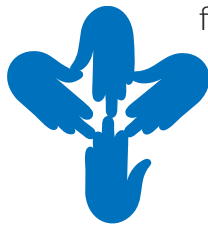
As the slum-police panchayats expand rapidly in Mumbai, training sessions are being organised for both police and community volunteers. Frequent reviews of past experience help chart out improvements for the future.

The plan, of course, is to go beyond just police rooms. The Alliance is currently exploring possibilities of the police room doubling as a doctor's consultation room or space for running adult literacy programs.

और अब 200 झोंपड़पट्टियों में हैं पुलिस सहायक

योजना के प्रवर्तन के एक वर्ष से भी कम समय में, मुंबई में 200 झोंपड़पट्टी पुलिस पंचायतें शुरू हो गयी हैं।

पुणे के नौ महिनों बाद मुंबई में पुलिस सहायक योजना का उद्घाटन हुआ। झोंपड़पट्टी पुलिस पंचायत में हैं झोंपड़पट्टी से 10 पुलिस सहायक (सात महिलायें, तीन पुरुष) और एक स्थानीय पुलिस अफसर। ये मिल कर इलाके में शांति बनाये रखते हैं। जैसे कि, पुलिस कमेटियों ने स्थानीय लोगों की अवैध शराब बनाती और बेचती 'दुकानों' को बंद करने के लिये दबाव डाला जिससे नशे में होने वाली मार पीट कम हुई। साथ ही स्थानीय महिला मिलन, अवैध शराब बनाने वालों को नई जीविका विकसित करने में मदद करती है। समुदाय स्वयंसेवकों के बिना पुलिस के लिये इस तरह के झगड़े नियंत्रित करना असंभव है।



MAKING CONNECTIONS:
India

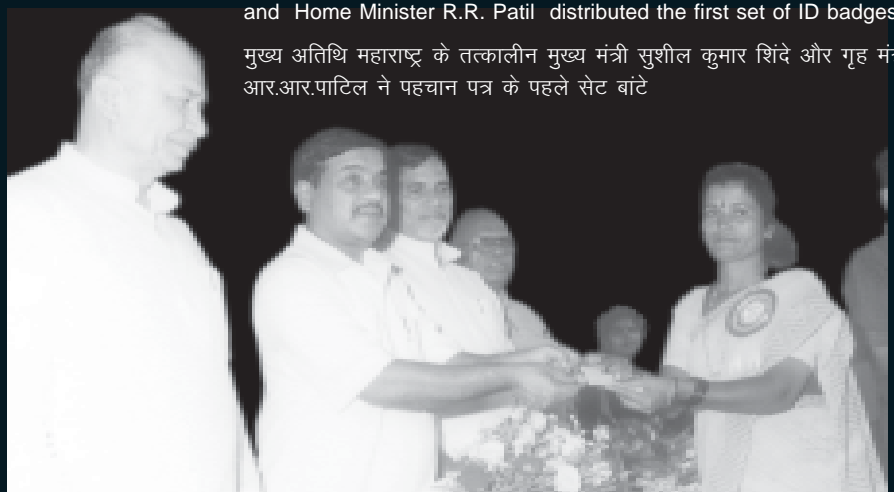
फैलते क्षितिज

जैसे जैसे मुंबई में झोंपड़पट्टी पुलिस पंचायतें तेजी से बढ़ रही हैं, पुलिस और समुदाय स्वयंसेवियों के लिये प्रशिक्षण सत्र किये जा रहे हैं। पुराने अनुभवों के बार बार अवलोकन भविष्य में सुधार लाने में सहायता करते हैं।

लेकिन इस योजना को सिर्फ पुलिस कमरे से निकल कर आगे जाना है। गठबंधन अभी विचार कर रहा है कि क्या पुलिस कमरे में डाक्टर की क्लिनिक या फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाये जा सकते हैं।

Chief guests then Maharashtra Chief Minister Sushil Kumar Shinde and Home Minister R.R. Patil distributed the first set of ID badges.

मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री सुशील कुमार शिंदे और गृह मंत्री आर.आर.पाटिल ने पहचान पत्र के पहले सेट बांटे



Members of Mahila Milan show off their Police Sahayak badges.

महिला मिलन की सदस्याएँ अपने पुलिस सहायक बैज दिखाते हुए।



प्रादेशिक संगठनों को और बल

दक्षिणी संगठनों के लिये हर महीने अलग अलग जगहों पर प्रादेशिक कार्यशालायें चलायी जायेंगी। यह निर्णय राष्ट्रीय नेताओं की जून मीटिंग में लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था कि हर शहर का संगठन अपने झोंपड़पट्टी सर्वे पूरे करे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हुए अपनी नगरपालिका को विस्तृत पत्र भेजे। वर्ष भर में राष्ट्रीय नेताओं का विशिष्ट दल प्रगति का अवलोकन करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत में संगठनों को सहारा देने हर शहर जायेगा।

नये संगठन – महाराष्ट्र के लातुर, सांगली, कोल्हापुर; तामिलनाडु के तारमपुरम, पल्लानी, बोदी, तिरुपुर; कर्नाटक में बीदर, हुबली, धारवाड़; उड़ीसा में कोणार्क और पश्चिम बंगाल में कोना – जो पिछले वर्ष एन.एस.डी.एफ. में आये, एक्सचेंज कार्यक्रमों के जरिये संगठन के तरीकों से परिचित कराये जायेंगे जिससे की वे अपने गुटों का विकास कर सकें। और अब जब गठबंधन को आंध्र प्रदेश में राज्यकीय स्वच्छता नीति बनाने को कहा जा रहा है, विजयवाड़ा और वाइजैग के संगठनों का मार्गदर्शन करने के लिये हैदराबाद के संगठनों को विशेष सहारा दिया जायेगा। यहां गठबंधन ने बड़ा शौचालय निर्माण कार्यक्रम हाथ में ले रखा है। एन.एस.डी.एफ. नासिक, अहमदनगर और अहमदाबाद संगठनों की भी सहायता कर

रहा है की वे बेदखल होने वाले समुदायों के पुनर्वसन पर चल रही बातचीत सशक्त कर सकें। प्रादेशिक संगठनों के नेता यह देखने मुंबई आये की महानगरी में पुनर्वसन किस प्रकार होता है। वर्तमान संगठनों को भी सहारा दिया जायेगा, विशेष रूप से चेन्नई, तिरुवल्लूर और बेंगलूर के संगठनों को कि वे पहले से संगठित झोंपड़पट्टियों में सदस्यता बढ़ायें।



Members of the Polur Mahila Milan meet every month with their counterparts from Arani, Tiruvannamalai and Chengam to share experiences. Their report on issues needing support is later presented to the Southern regional workshop.

पोलुर महिला मिलन के सदस्य हर माह अरणी, तिरुवन्नमलई और चेंगम के सदस्यों से मिलती हैं अपने अनुभव बांटने और दक्षिण प्रादेशिक कार्यशाला को रिपोर्ट देने कि किन मुद्दों पर उन्हें सहायता की जरूरत है

More Strength to Regional Feds

REGIONAL workshops will be held every month in different locations for Southern federations, it was decided at a June meeting of nationwide leaders.

Another important decision taken was for each city federation to complete its slum surveys and send detailed letters to its municipality, initiating a conversation on various issues. Over the year, a core group of national leaders will visit each city to review progress and support federations in their discussions with local authorities.

The new federations (Latur, Sangli, Kolhapur in Maharashtra, Tarampuram, Pallani, Bodi, Tirupur in Tamil Nadu, Bidar, Hubli, Dharwar in Karnataka, Konarak in Orissa and Kona in West Bengal) which joined NSDF last year will be supported, through exchange programs, to become more familiar with Federation strategies and build their groups. And, with the Alliance being asked to get involved with different cities in AP, the Hyderabad federations will get special support to guide federations in Vijaywada and Vizag, where the Alliance has taken up large toilet construction programs.

NSDF is also helping the Nasik, Ahmednagar and Ahmedabad feds strengthen their dialogue on resettlement of communities faced with eviction. Regional fed members visited Mumbai to study how resettlement was managed in the metropolis.

Existing federations too will be supported to expand membership within already federated slums, particularly the city level federations in Chennai, Thiruvalluvar and Bangalore.

गठबंधन शहरी सलाहकार समिति का सदस्य है

पिछले अक्टूबर में भारत सरकार के नागरी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव चित्रा चोपड़ा ने गठबंधन को आमंत्रित किया कि वे शहरी नीति गोष्ठी की सलाहकार समिति में आयें। यह समिति राज्य शहरी विकास सचिवों का मार्गदर्शन करेगी।

गोष्ठी के सदस्यों में अवकाशप्राप्त मुख्य सचिव, नगरपालिका आयुक्त और महापौर भी हैं। ये शहरी मुद्दों पर विचार करने के लिये 4-6 महीनों में एक बार मिलते हैं।

गठबंधन मुंबई टास्क फोर्स के आवास ग्रुप एवं सिटिजनस् एक्शन ग्रुप का भी सदस्य है। ये दोनों मुंबई के प्रभावशाली नागरिकों के मंडल हैं जो मुंबई की उन्नति के लिये साथ आये हैं।

Alliance is Member of Urban Advisory Group

LAST October, the Alliance was invited by Chitra Chopra, Secretary of the Ministry of Urban Poverty, Alleviation & Employment, GoI, to join the Urban Policy Forum advisory group, which will guide State Urban Development Secretaries.

Forum members include retired chief secretaries, municipal commissioners and mayors. The Forum meets once every 4-6 months to address a wide range of urban issues.

The Alliance is also a member of the Housing Group of the Mumbai Task Force as well as of the Citizens Action Group. Both these comprise influential citizens of Mumbai who have come together to re-envision the city.

Community functions and festivals go a long way towards strengthening bonds and appreciating each other's cultures. Earlier, most women did not even know their neighbours even from five houses away!

समुदाय के कार्यक्रमों और त्योहारों का बहुत योगदान है बंधन मजबूत करने और एक दूसरे की संस्कृति जानने की ओर। पहले अधिकतर महिलायें अपने से पांच घर दूर वाले पड़ोसी को भी नहीं पहचानती थीं।

Saying It With Flowers...and Sweets

ONE of the NSDF'S oldest traditions is for Mahila Milan leaders from various communities across the city to visit each other on festival days to share sweets, flowers and stories. Whether it's *haldi kumkum* celebrations where married Hindu women distribute jasmine *venis* and eat specially prepared foods or *iftar* parties where Muslim communities gather for dinner after a long day's fast, such community functions go a long way towards strengthening bonds and appreciating each other's cultures.

"Haldi kumkum festivals are important because most of our members are women and we celebrate their functions publicly," says Isaac Lopez, a community organizer who has been working with the Panvel and Raigad federations for the last decade. "When women come together for these occasions, they are relaxed, they have fun, but they also share all their other problems related to their families and, this way, grow closer."

The Federation has come a long way. Twenty years ago, when the first Mahila Milan group was formed, the women realized that most people did not know their neighbours even from five houses away! However they soon realized the importance of working together – whether it was for meeting a municipal official for a ration card or confronting demolition squads! Rituals like the *haldi kumkum* and *iftar* parties celebrate the spirit of people's unity.

“फूलों से, मिठाई से.... हमारा कहना है”

एन.एस.डी.एफ. की सबसे पुरानी परम्पराओं में से एक है कि त्योहारों के दिन, शहर के अलग अलग भागों से महिला मिलन नेता एक दूसरे से मिलती हैं और आपस में मिठाइयां, फूल और कहानियां बांटती हैं। “हल्दीकुमकुम त्योहार महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी अधिकतर सदस्य महिलाएं हैं” कहना है इसाक लोपेज़ का, जो एक समुदाय संगठनकर्ता हैं और पिछले दशक से पनवेल और रायगढ़ संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। “जब महिलाएं इन कार्यक्रमों के लिए साथ आती हैं, वे तनावमुक्त होती हैं, वो मजा करती हैं, पर वो आपस की पारिवारिक समस्याएं भी एक दूसरे से बाँटती



हैं और इस तरह और निकट आ जाती हैं”। संगठन ने लंबी दूरी तय कर ली है। बीस वर्ष पहले, जब पहला महिला मिलन गुट बनाया गया था, महिलाओं को पता चला की अधिकतर लोगों को अपने से पाँच घर दूर के पड़ोसी की भी जानकारी नहीं थी! लेकिन जल्द ही उन्हें साथ काम करने का महत्व पता चल गया – चाहे नगरपालिका अधिकारी से राशन कार्ड के लिए मिलना हो या डेमोलिशन वालों का सामना करना हो! हल्दी कुमकुम और इफ्तार जैसे रिवाज उनकी एकता की भवना को मनाते हैं।



Now, Capacity-Building Scholarships!

AN IMPORTANT aspect of local capacity building is supporting young people from slum communities to achieve their academic and professional aspirations. This support is vital to ensure that the Federation process is sustainable in the long run.

NSDF and RSDF (Railway Slum Dwellers Federation) have accordingly funnelled the Mariwala Trust grant of Rs. one lakh into scholarships for 13 young and promising school and college students from Dharavi, resettlement communities in Mankhurd, and pavement communities in Byculla.

The 2004 scholarships went to two high school and five college students, five attending technology institutes/polytechnics and one student of the Institute of Chartered Accountants of India.



गठबंधन के लिए नया अवलोकन तरीका

स्पा र्क की संस्थापक—सदस्या श्रीलता बाटलीवाला आजकल हार्वर्ड के हाउसर सेंटर फॉर नॉन प्रोफिट ओर्गनाइजेशन में शोधकर्ता हैं। वे अगले दो वर्षों में गठबंधन के समुदाय प्रेरित शहरी कार्यक्रमों के लिए एक नया विश्लेषण और मूल्यवान तंत्र बना कर लागू करेंगी। वे लेखन के तरीकों को नये सिरे से विस्तृत कर, आसानी से काम में आनेवाला बनाएंगी (देखिए कोष्ठक)। यह तरीका गठबंधन की प्रगति के बारे में आंतरिक शिक्षा और जानकारी को बढ़ावा देगा। इससे समुदाय प्रेरित संसाधन परियोजनाओं की प्रक्रियाओं के बारे में आंतरिक जानकारी मिलेगी (जो कि भविष्य के परामर्श और नीतियों में योगदान देगी) साथ ही बाहरी दर्शकों और मूल्यांकनों के लिए भी मज़बूत और तथ्यपूर्ण सामग्री मिलेगी।

New Review System for Alliance

OVER the next two years, SPARC founder member Srilatha Batliwala, currently Research Fellow at Harvard's Hauser Center for Nonprofit Organizations, will help design and implement a new monitoring and evaluation system for the Alliance's community-led urban programmes. She will revamp the documentation system to make it exceedingly comprehensive and easily accessible. (See box)

The system will promote effective internal learning and information regarding the Alliance's progress. It will offer insights on the process of community-led infrastructure projects (which can contribute to future advocacy and policy) as also sound and rigorous data for external audiences and evaluations.

Introducing SPARCLE!

THE enormous amount of verbal, written and visual data, collected by the Alliance over the last two decades, and representing a rich and deep institutional history, will be reorganised for easy access by different audiences.

Discussions with Consultant Srilatha Batliwala, who will implement and oversee the project, threw up a winning name for the new-look database – SPARCLE!

स्पा र्कल से परिचय!

पिछले दो दशकों में गठबंधन द्वारा एकत्रित प्रचुर मौखिक, लिखित और दर्शक सामग्री, जो कि उसके इतिहास का गहरा और समृद्ध प्रस्तुतिकरण है, अलग अलग दर्शकों के लिए सरलता से उपलब्ध करायी जाएगी।

इस योजना का संचालन और देखरेख करनेवाली परामर्शदाता श्रीलता बाटलीवाला ने बातचीत के दौरान इस नए डाटाबेस का नाम सुझाया – स्पा र्कल! (यानी चमक)



और अब, क्षमता बढ़ाने वाली छात्रवृत्तियां

स्था नीय क्षमता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आयाम है झॉपड़पट्टी समुदाय के युवाओं को उनकी पढ़ाई और व्यायसाय सम्बंधी इच्छाएँ पूरी करने में सहारा देना। यह सहारा जरूरी है क्योंकि आगे जा कर इसी से संगठन प्रक्रिया चलती रहेगी।

एन.एस.डी.एफ और आर.एस.डी.एफ (रेलवे झॉपड़पट्टीवासीसंगठन) ने यही सोच करे मरीवाला ट्रस्ट की एक लाख रुपए की ग्रांट को छात्रवृत्तियों के लिए रखा है जो धारावी और मानखुर्द के पुनर्वसित समुदायों, और भायकला के फुटपाथ समुदायों के 13 युवा और होशियार स्कूल या कॉलेज के बच्चों को दी जाएगी। 2004 में छात्रवृत्तियां दो उच्च माध्यमिक स्कूल और पांच कॉलेज के छात्रों को, पाँच टेक्नोलोजी संस्थाओं या पोलिटेक्निक के छात्रों को और एक भारतीय चार्टर्ड आकाउंटेंट संस्था के छात्र को दी गई।

SPARC founder-member Srilatha Batliwala (center), while teaching at Harvard, used the Alliance's work at Rajiv Indira and its partnership with Citibank as one of her case studies on financial institutions and poor communities working together. This was later used by the business school at the Kennedy School of Government. Above, Batliwala being garlanded at the NSDF Annual Convention.

स्पा र्क की संस्थापक सदस्या श्रीलता बाटलीवाला ने हार्वर्ड में पढ़ाते समय गठबंधन का राजीव इंदिरा में किया गया काम और वित्तीय संस्थाओं और गरीब समुदायों के मिल कर काम करने पर और सिटीबैंक से उसकी भागीदारी का विशेष अध्ययन कराया। इसे बाद में केनेडी स्कूल के प्रबंध विभाग ने भी काम में लिया। ऊपर, बाटलीवाला को एन.एस.डी.एफ. के वार्षिक अधिवेशन में माला पहनायी गयी।



Mahila Milan Rings in World Microcredit Year at BSE

ON 18th November 2004, United Nations' World Microcredit Day, micro-entrepreneurs across the world rang their country stock exchange opening bells to announce the launch of World Microcredit Year.

In India's largest – the Bombay Stock Exchange, powerhouse of India's financial world – six 'Mahila Milan-ers' (from Byculla pavements and the Mankhurd and Wadala resettlement sites) rang the bell precisely at 9.55 a.m. to mark the start of trading.

The BSE event was organized by the CitiGroup, NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development), Planet Finance, a non-profit organisation headquartered in France, and the Bombay Stock Exchange.

The stock exchanges were chosen as inaugural sites so as to drive home the importance of liberalizing financial systems for both rich and the poor, and the fact that micro-entrepreneurs are dynamic economic contributors.

"Let us be clear: micro-finance is no charity," said UN Secretary-General Kofi Annan, in a message read out at the ceremony, "It is a way to extend the same rights and services to low-income households that are available to everyone else."

Veteran Mahila Milan leader from Byculla, Laxmi Naidu, urged the audience at BSE – comprising mainly bigwigs from India's financial sector – to see Mahila Milan's work for themselves. "We have been pooling our savings and supporting our communities for the last 20 years. That's how we can talk to banks today on what services we need." Sheela Patel, Director-SPARC, spoke of the Alliance's long-standing relationship with CitiGroup, "Relationship building is an important aspect of support from corporates. We learnt to talk to banks and financial agencies through our sustained engagement with CitiGroup." She added, "For the Alliance, today's event symbolises the commitment of the city's poor to participate in its transformation."

महिला मिलन लायी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में विश्व माइक्रो क्रेडिट वर्ष



टारह नवम्बर 2004 को यू.एन. विश्व माइक्रो क्रेडिट दिवस पर, संसार भर के लघु-उद्योगपतियों ने अपने अपने देशों के शेयर बजारों की प्रारंभिक घंटियां बजा कर विश्व माइक्रो क्रेडिट वर्ष के शुरु होने की घोषणा की।

ऐशिया के सबसे बड़े और भारतीय वित्त की दुनिया के चालक मुंबई शेयर बजार में – भायखला के फुटपाथ और मानखुर्द और वडाला पुनर्वसन स्थलों से छः महिला मिलन की महिलाओं ने सुबह 9.55 होते ही घंटी बजाई जिससे खरीद-फरोख्त शुरु हो सके।

इस उद्घाटन के लिये शेयर बजारों का चयन इसलिये किया गया कि इस बात को महत्व दिया जा सके की अमीर और गरीब दोनों ही के लिये वित्तीय व्यवस्थाएँ मुक्त हो रही हैं और यह भी कि लघु-उद्योगपति भी सक्रिय आर्थिक योगदान देते हैं।

मुंबई शेयर बजार का कार्यक्रम सिटी ग्रुप, नाबार्ड, प्लॉनेट फाइनेंस (गैर लाभकारी संस्था जिसका मुख्यालय फ्रांस में है) और मुंबई शेयर बाजार ने आयोजित किया।

'हम यह स्पष्ट कर लें : लघु वित्त कोई परोपकार नहीं है,' यू.एन. मुख्य सचिव कोफी आन्नान ने समारोह में पढ़े गये संदेश में कहा, 'यह एक तरीका है कम आय के परिवारों को वही अधिकार और सेवायें दिलाने का जो बाकी सब को उपलब्ध हैं'।

भायखला की अनुभवी महिला मिलन नेता लक्ष्मी नायडू ने बी.एस.ई. में उपस्थित दर्शकों (जो की मुख्यतः भारत के वित्तीय क्षेत्र की हस्तियां थे)

से अनुरोध किया कि वे स्वयं महिला मिलन के काम को देखें। "हम लोग पिछले 20 सालों से अपनी बचत एक ही जगह इकट्ठी करते हैं और अपने अपने समुदायों को सहारा दे रहे हैं। इस के लिये आज हम बैंको से बात कर सकते हैं कि हमें किन संसाधनों की जरूरत है", स्पार्क की

डायरेक्टर, शीला पटेल ने सिटी ग्रुप के साथ गठबंधन के पुराने संबंधों की बात की, "बड़े समूहों या कॉरपोरेट्स

का सहारा लेने का महत्वपूर्ण आयाम है उनसे संबंध बनाना। सिटीग्रुप के साथ अपने लगातार संबंधों के कारण हमने बैंको और वित्तीय संस्थाओं से बात करनी सीखी। उन्होंने यह भी कहा, "गठबंधन के लिये आज का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि शहर के रूपांतरण में गरीब अपनी भागीदारी के प्रति कटिबद्ध हैं।"

"Micro-finance is a way to extend the same rights and services to low-income households that are available to everyone else." – Kofi Annan, UN Secretary General

"माइक्रो फाइनेंस एक तरीका है कम आय के परिवारों को वही अधिकार और सेवायें दिलाने का जो बाकी सब को उपलब्ध हैं" – यू.एन. मुख्य सचिव कोफी आन्नान



Macro-Concern – Not Just Micro-Credit

“WE ARE not a micro-credit organisation – we do not have 99% credit recovery,” SPARC clarifies in reply to bank enquiries about Mahila Milan’s savings and credit systems. “Our focus is on assisting the poor build their own finances for housing and infrastructure – at their own pace.”

Visiting bankers are told firmly by leaders at the Byculla office, “If a person cannot pay, we don’t punish them. We always try and find out the reason for non-payment. And if it’s a real problem, we will give her another loan to help. If we don’t help her, who will?”

If the bankers still stay interested, a Mahila Milan leader takes them on the traditional savings round. Usually most people come back very impressed. But when they sit down with Mahila Milan leaders and admin staff to examine the systems of record-keeping, they realise that the credit systems have organically evolved with emphasis on supporting the very poor access cheap loans.

Since linking with banks is an important opportunity to up-scale finance available to the poor, efforts are now underway to strengthen and standardise repayments.

बड़े मुद्दे – लघु ऋण नहीं

“हम लघु-ऋण संस्था नहीं हैं – हमारी उधार वसूली 99 प्रतिशत नहीं है,” स्पार्क स्पष्ट करता है जब बैंक महिला मिलन की बचत और ऋण के तरीकों के बारे में पूछते हैं। “हमारे काम का केंद्र है आवास और संसाधन निर्माण करने के लिये गरीबों को वित्त जुटाने में मदद करना। वो भी उनकी अपनी गति से।

भायखला ऑफिस के नेता मिलने आये बैंक वालों को दृढ़ता से बताते हैं, “यदि कोई उधार नहीं चुका सकता हम उसे सजा नहीं देते। हम हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं की भुगतान क्यों नहीं हुआ और अगर सच में तकलीफ है तो हम उसे दूसरी बार भी उधार देते हैं। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा?”



Whichever the city, the ritual of daily collection of savings and loans and recording them at the local Area Resource Center goes on like clockwork.

शहर कोई भी हो, दैनिक बचत और ऋण एकत्रित करने का काम और उसे स्थानीय एरिया रिसोर्स सेंटर में लिखवाने का काम घड़ी के जैसे चलता है।

यदि बैंक वालों को फिर भी दिलचस्पी होती है तो एक महिला मिलन नेता उन्हें पारम्परिक बचत चक्कर पर ले जाती है। अधिकतर लोग बहुत प्रभावित हो कर आते हैं। पर जब वे महिला मिलन नेताओं और ऑफिस के कर्मचारियों के लेखे-जोखे के तरीके देखने बैठते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह ऋण की व्यवस्था बहुत ही गरीब को सस्ते ऋण दिलाने की दृष्टि से सहज रूप से विकसित हुई है। वैसे गठबंधन को अहसास है कि बड़े व्यक्तिगत ऋण लेने के लिये बैंकों से नाता जोड़ना, गरीबों को मिलने वाले वित्त को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। साथ ही भुगतान के तरीकों को मजबूत और मानक बनाने का प्रयास जारी है जिससे जरूरतमंद लोग, जो कठिन भुगतान स्कीम वाले बड़े बैंक ऋण लेने की क्षमता रखते हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

Strengthening Internal Systems

WHILE the Alliance explores partnerships with various financial institutions, it is also aware that for communities to take on and repay large loans, their internal management systems need to be upgraded.

Since July '04, a Central Loan Committee, comprising five Mahila Milan leaders from resettled communities has been coordinating all savings, loans and collections. Reporting to them are teams of young college girls who get a small stipend for visiting each house everyday to collect savings. All daily collections are credited to a joint account overseen by an NSDF co-ordinator and two women from the central committee. A monthly review is

done by SPARC along with the Mahila Milan and administrative teams.

Since the new loans from banks will be much larger than the loans given out so far, it is important to walk Mahila Milan members through the daily repayment collections and interest calculations. Unlike MM loans, where the principal is repaid first, and interest charged later at 2% a month, the bank loans will require the principal and interest payments to be paid simultaneously.

For the Alliance, this is a very important process as poor communities enter the formal financial world and learn to tackle problems and complexities right from the start.



आंतरिक तरीके मजबूत करना

जहां एक ओर गठबंधन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ भागीदारी करने की सोच रहा है, दूसरी ओर उसे यह भी पता है कि यदि समुदायों को बड़े ऋण लेने और वापस देने हैं तो उनकी आंतरिक व्यवस्थाओं को कसना होगा।

जुलाई 04 के बाद से पुनर्वसित समुदायों की 5 महिला मिलन नेताओं से बनी केन्द्रीय ऋण समिति सारी बचत, ऋण और भुगतानों की देखरेख कर रही है। उन्हें रिपोर्ट करते हैं कॉलेज की लड़कियों के दल जिन्हें रोज हर घर में जा कर बचत एकत्रित करने के लिये छोटसा मेहनताना दिया जाता है। हर दिन की जमा राशी एक साझाखाते में डाली जाती है जिसकी देखरेख केन्द्रीय समिति की दो महिलायें और एक एन.एस.डी.एफ. का संयोजक करते हैं। स्पार्क, महिला मिलन और व्यवस्था दल मिल कर हर महिने इनका निरीक्षण करते हैं।

बैंकों से मिलने वाले नये ऋण अभी तक मिले ऋणों से काफी बड़े होंगे : इसलिये यह जरूरी है कि महिला मिलन सदस्यों को दैनिक भुगतान इकट्ठे करने और ब्याज की गणना करनी बतायी जाये। महिला मिलन ऋण में पहले मूल का भुगतान होता है फिर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाता है लेकिन बैंक ऋण में मूल और ब्याज दोनों के भुगतान साथ साथ करने पड़ेंगे।

यह गठबंधन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे गरीब समुदाय औपचारिक वित्त की दुनिया में कदम रखें वे शुरू से ही समस्याओं का सामना करना सीख लें।

Banks & Poor Jointly Explore Housing Finance

ALTHOUGH the Alliance takes bulk loans for Mahila Milan to on-lend for livelihood and consumption activities, as the NSDF's capacity and outreach has grown, so has its members' demand for housing finance. The only institutions capable of meeting this demand are from the banking sector.

However, few precedents exist of successful partnership between banks and organisations of the poor because of mutual distrust. As a result, a major goal of the Alliance is to create a bridge between the poor and the banks and create a viable model that can be replicated on scale.

The Alliance does have some experience with private banks. In 1998, Citibank gave it a loan for a multi-storey housing project in Dharavi, Mumbai's largest slum. Some years later, UTI Bank provided a guarantee for a Rs. 44 crore sanitation contract awarded to the Alliance.

Although both these relationships were significant, a lot remains to be done in the areas of mainstream housing and sanitation finance. Federated groups require finance in two main areas. Firstly, bridge-finance or loans for self-financing projects where payments come in at the end of a project (whether housing or sanitation). Secondly, individual or group loans for housing cooperatives of slum dwellers who wish to access low-income housing and demonstrate their ability to repay loans.

It's encouraging to note that banks are beginning to look at the poor as potential customers. As the Alliance fine-tunes its credit management systems and diversifies its applications for finance, as you can see from the following, a variety of banks are extending a hand in partnership –

बैंकों और गरीबों ने मिल कर आवासीय वित्त निरीक्षण किया

गठबंधन थोक में ऋण लेता है जिसे महिला मिलन (जीवीका कमाने और रोजगार की जरूरतों के लिये) आगे वितरित करती है। लेकिन जैसे जैसे एन.एस.

डी.एफ. की क्षमता बढ़ी है वैसे वैसे आवास वित्त के लिये

उसके सदस्यों की मांग बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने की ताकत

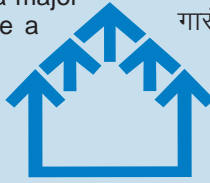
सिर्फ बैंकों में है।

लेकिन बैंकों और गरीबों के संगठनों के बीच सफल भागीदारी के उदाहरण बहुत कम हैं क्योंकि दोनों में आपसी विश्वास नहीं है। इसके परिणामस्वरूप गठबंधन का एक बड़ा लक्ष्य है गरीबों और बैंकों के बीच की खाई पाटना और एक ऐसा व्यवहारिक मॉडल बनाना जो बड़े स्केल पर दोहराया जा सके।

गठबंधन को निजी बैंको का कुछ अनुभव है। 1998 में सिटिबैंक ने उसे मुंबई की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी धारावी में स्थित कई मंजिली आवास परियोजना के लिये ऋण दिया था। दूसरी बार कुछ सालों बाद यू.टी.आई. बैंक ने गठबंधन को मिले एक 44 करोड़ के शौचालय ठेके के लिये गारंटी दी थी।

हालांकि दोनों संबंध काफी महत्वपूर्ण थे, आवास और शौचालय वित्त के क्षेत्रों में काफी कुछ करना बाकी है। संगठित गुटों को दो मुख्य क्षेत्रों में वित्त की आवश्यकता होती है। पहला, ब्रिज फाइनेंस या ऋण, ऐसी स्वयं-वित्त योजनाओं के लिये जहां (चाहे आवास हो या शौचालय) भुगतान परियोजना के पूरी होने के बाद में होता है। दूसरा, व्यक्तिगत या ग्रुप ऋण, झोंपड़पट्टीवासियों के सहकारी घरों के लिये, ऐसे लोगों के लिये जो कम आय घरों में जाना चाहते हैं और ऋण चुकाने की क्षमता दिखाते हैं।

इस बात से प्रोत्साहन मिलता है कि बैंकों ने गरीबों को भावी ग्राहकों के रूप में देखना शुरू किया है। जैसे जैसे गठबंधन अपने ऋण प्रबंधन तरीके सुधारता है और वित्त के लिये अपनी योजनाओं में विविधता लाता है (जैसे की आप आगे देख सकते हैं), कई तरह के बैंक इसकी ओर भागीदारी का हाथ बढ़ा रहे हैं।



New Directions



Oshiwara 1

ओशिवारा 1



राष्ट्रीय आवास बैंक ने ऋण के लिये हरी झंडी दिखाई

नवम्बर 2004 में राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) ने पांच वर्ष के लिये 6.5 प्रतिशत की दर से रु. 5.89 करोड़ का ऋण भारत जनता गृह निर्माण संस्था के लिये मंजूर किया। यह 147 परिवारों की संस्था है जो अपनी जमीन पर पांच बहुमंजिली इमारतें बना रही है। इस केस में कुछ अलग यह हुआ की एन.एच.बी. स्वयं गठबंधन के पास आया। उप-प्रबंधक खेडकर ने मार्च 2003 में स्पार्क द्वारा आवासीय वित्त पर आयोजित एक वर्कशॉप में भाग लिया और वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बैंक को मनाया की वह गठबंधन के बारे में विचार करे। अधिक से अधिक गरीबों को आवासीय वित्त उपलब्ध कराने के अधिदेश के चलते एन.एच.बी. ने मुख्यतः दूसरे बैंकों को ही वित्त दिया है, शहरी गरीबों को सीधे उधार देने का उनका कोई अनुभव नहीं है। हालांकि, जैसे की एन.एच.बी. प्रतिनिधियों ने बताया, इसके लिये अलग से साधन रखे गये हैं, गरीबों को ऐसे ऋण देने में किसी बैंक की रुचि नहीं दिखी। इसलिये उन्होंने निश्चय किया के वे स्वयं संभावनायें ढूँढ़ेंगे।

गठबंधन के लिये यह एक बड़ा कदम है। महज यही तथ्य की देश का एक सर्वोच्च आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक बैंक – सकारात्मक तरीके से – कम आय वाले आवास को ऋण उपलब्ध कराने के बारे में सोच रहा है तो अन्य बैंकों को स्पष्ट सिगनल मिलता है की वे भी इस बारे में सोचें।

आइ.सी.आइ.सी.आई. साथ आया

मध्य 2004, में आइ.सी.आइ.सी.आई. ने गठबंधन के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई थी और वह मिल कर देखने के लिये तैयार थे कि वे किस तरह गठबंधन को सहारा दे सकते हैं। सुयोग से बातचीत के कुछ ही महीनों बाद गठबंधन को आज तक की सबसे बड़ी आवासीय परियोजना प्रस्तुत की गयी, ओशिवारा-2 जहां झोंपड़पट्टीवासीयों के पुनर्वसन के लिये 2000 आवास निर्माण करने थे।

आइ.सी.आइ.सी.आई. के प्रतिनिधी सारे जमीनी काम में गठबंधन के साथ रहे, जगह पर आने वाली समस्याओं से निपटने में और जमीन के मालिकों और समुदायों दोनों से बातचीत करते रहे। उन्होंने ये तो देखा ही की सारी प्रक्रिया कितनी जटिल है; उनमें गठबंधन की क्षमताओं के प्रति भी विश्वास पैदा हो गया। मार्च 2005 में आइ.सी.आइ.सी.आई. बैंक ने अनौपचारिक रूप से गठबंधन की निर्माण संस्था 'निर्माण' को 20 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है। इस राशि के लिये गारंटी होमलेस इंटरनैशनल देगी।

Bharat Janata
भारत जनता

National Housing Bank Green Signals Loan

In November 2004, the National Housing Bank (NHB) sanctioned a five-year loan of Rs. 5.89 crores at 6.5% for the Bharat Janata Housing Co-operative. This is a settlement of 147 families who are constructing five multi-storey buildings on their land.



Money-matters

Somewhat unusually, in this case, it was the NHB that approached the Alliance. Dy. Manager Khedkar, who had attended a workshop on housing finance hosted by SPARC in March '03, was so impressed that he convinced his bank to start looking at the Alliance. With a mandate to widen access to finance for housing for the poor, NHB has primarily refinanced other banks and has little experience in lending directly to the urban poor. Although, as NHB reps pointed out, they have a dedicated sum of resources for this, they found no banks interested in such lending. So they opted to explore possibilities themselves.

This is a big step ahead for the Alliance. The fact that one of the apex housing banks in the country – a subsidiary of the Reserve Bank of India – is proactively looking at funding low-income housing sends a clear signal to other banks to explore similar activities.

ICICI Gets on Board...

MID-2004, ICICI expressed a keen interest in working with the Alliance and was willing to jointly explore how it could best support the Alliance. Opportunely, just a few months after discussions took off, the Alliance was offered its largest housing project to date – Oshiwara 2 – where 2000 tenements were to be constructed to re-house slum dwellers. So ICICI reps walked alongside the Alliance through all the groundwork, addressing problems on site, and inter-acting with land owners as well as communities. Not only did they see for themselves how complex the process really is, they developed confidence in the Alliance's capabilities.

March 05, the ICICI Bank informally approved a loan of Rs. 20 crores to Nirman, the Alliance's construction wing. Homeless International will provide a guarantee for this amount.



Building on Friendly Ties with UTI Bank

THE Alliance's relationship with UTI Bank goes back in time. A few years ago, they provided a financial guarantee for a large-scale sanitation project the Alliance was undertaking.

Recently, the relationship has taken another step forward. A dozen young bankers, interested in learning about Alliance work and supporting its financial systems, have been assigned – two each – to various projects. It is expected that this collaboration will sharpen Alliance skills in presenting projects to banks.

Alliance to Set Up Bankers' Forum

AS THE Alliance's engagement with formal financial institutions expands, it has become important to document the experience in a manner easily replicated by other members of the banking fraternity as also the development sector.

To this end, the Alliance is setting up a Bankers' Group, comprising senior officials from leading private and nationalised banks, who will study the Alliance's work, guide it through financial and risk assessments, then help translate the whole into 'Bankerese' for others. Another major step towards mainstreaming low-income housing loans.

Dialoguing with RBI

WHILE on one hand the Alliance works with private and nationalised banks to encourage them to lend to the urban poor, on the other, it also regularly dialogues with regulatory bodies such as the Reserve Bank of India to create mechanisms for the poor to access housing finance.

For the most part, RBI has been very responsive to the Alliance and since 2004, has been taking cognizance of its work in different projects. Recently, the lead bank invited the Alliance to make a presentation of its work to a Task Force (appointed by the Ministry of Finance) to examine ways to extend financing to non-conventional projects. SPARC's Sheila Patel and Sundar Burra, NSDF Prez A. Jockin and Nirman Chairman Vijay Aggarwal participated in the meeting chaired by the Jt. Secretary from the Ministry of Finance.

यू.टी.आई. के साथ दोस्ती के रिश्ते

यूटी.आई. के साथ गठबंधन का रिश्ता कई साल पुराना है। कुछ साल पहले उन्होंने गठबंधन द्वारा की जा रही बड़े पैमाने की शौचालय परियोजना के लिये वित्तीय गारंटी दी थी। हाल में यह रिश्ता और आगे बढ़ा है। लगभग एक दर्जन युवा बैंकर हैं जो गठबंधन के काम के बारे में सीखना चाहते हैं और उसके वित्तीय तरीकों को सहारा देना चाहते हैं। उन्हें –दो दो कर के– विभिन्न परियोजनाओं में भेजा गया है, आशा करते हैं कि इस सहयोग से बैंकों के समक्ष परियोजनायें प्रस्तुत करने की गठबंधन की निपुणता बढ़ेगी।

गठबंधन बनायेगा बैंकवालों की गोष्ठी

जैसे जैसे औपचारिक वित्त संस्थाओं से गठबंधन का मेलजोल बढ़ रहा है, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि इस अनुभव का लेखन किया जाये जिससे की अन्य बैंक वाले और विकास के क्षेत्र वाले आसानी से इसकी नकल कर सकें।

इस दृष्टि से, गठबंधन एक बैंकवालों का ग्रुप बनायेगा जिसमें होंगे प्रमुख निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अफसर, जो कि गठबंधन के काम का अध्ययन करेंगे, वित्त और जोखिम का मूल्यांकन करेंगे और फिर औरों के लिये इस सब का अनुवाद बैंकीय भाषा में करेंगे। कम-आय के आवास ऋण मुख्यधारा में लाने की ओर यह एक और बड़ा कदम है।

रिजर्व बैंक के साथ वार्ता

एक ओर तो गठबंधन निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ काम करता है और उन्हें शहरी गरीबों को ऋण देने के लिये बढ़ावा देता है, दूसरी ओर वह भारतीय रिजर्व बैंक जैसी नियामक संस्थानों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है जिससे की गरीबों तक आवासीय वित्त पहुंचाने के नये तरीके बनाये जा सकें।

अधिकांश समय, आर.बी.आई. गठबंधन की तरफ बहुत अनुकूल है और 2004 के बाद से विभिन्न परियोजनाओं में उसके काम को देख रहा है। हाल ही में, इस प्रमुख बैंक ने गठबंधन को अपने टास्क फोर्स (वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त) के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने और तरीके ढूँढने के लिये आमंत्रित किया कि गैर-पारम्परिक योजनाओं को किस प्रकार वित्त दिया जा सकता है। शीला पटेल, सुन्दर बुर्रा, एन.एस.डी.एफ. अध्यक्ष ए. जोकिन और निर्माण के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने मीटिंग में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के उप-सचिव ने की थी।



Mahila Milan gives loans for housing finance – which members pay back at their own pace.

महिला मिलन आवासीय वित्त के लिये ऋण देती है – जिसे सदस्य अपनी गति से वापस चुकाते हैं।



ऐशियन बैंक ने गठबंधन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये



ऐशियन डेवेलपमेंट बैंक ने गठबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत वे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपीन्स और भारत में सम्पूर्ण गरीबी निवारण के लिये स्थानीय संस्थाओं को सहारा देंगे। योजना एस.डी.आई. की छत्रछाया में कार्यान्वित होगी।

इसके पहले, जुलाई 04 में ऐशिया एवं अफ्रीका के एक एस.डी.आई. दल ने मनीला में ऐशियन डेवेलपमेंट बैंक के व्यवसायिकों के साथ दिन बिताया। उन्होंने झोंपड़पट्टियों में गरीबी और विभिन्न देशों के एस.डी.आई. संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त विकास तरीकों के बारे में बात की। यह बातचीत बारसीलोना में डब्ल्यू.यू.एफ. में जारी रही। इस आदान प्रदान ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि झोंपड़पट्टी नेताओं और बहुपक्षीय संस्थाओं के व्यवसायिकों के बीच नियमित रूप से बातचीत होनी चाहिये जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें।



MM leader Hemlata Ardu addresses ADB audience on her resettlement experience.

महिला मिलन नेता हेमलता अरदू ने ए.डी.बी. श्रोताओं को अपना पुनर्वसन अनुभव बताया।

Asian Bank Signs MOU with Alliance

THE Asian Development Bank (ADB) has signed an agreement with the Alliance to support local organisations in Indonesia, Vietnam, the Philippines and India for integrated poverty alleviation. The project will function under the overall umbrella of the SDI.

Earlier, in July '04, an SDI team from Asia and Africa spent a day in Manila with ADB professionals, to discuss poverty in slums and development approaches employed by SDI affiliates in their various countries, with particular focus on the role of women. This discussion was followed up at the WUF in Barcelona.

The exchanges underlined the need for systematic interaction between slum leaders and professionals in multilateral institutions, to understand each other better.

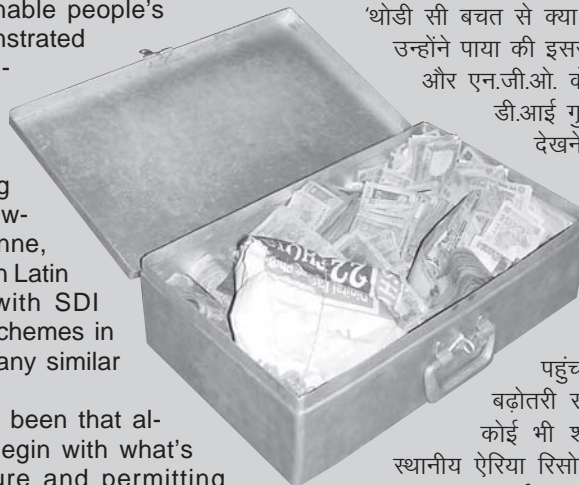
From 'What Can Modest Savings Achieve?' to 'Modest Savings Can Achieve!'

OVER 26 groups of community leaders, NGO managers of funds, bilateral agency personnel and city reps from Asia, Latin America and Africa, put their heads together to discuss various ways of managing community funds. The June 11 and 14th meetings were hosted by the Asian Coalition of Housing Rights (ACHR), Bangkok, and International Institute for Environment and Development (IIED), London.

The connection between daily savings, strong community processes and a sustainable people's organisation were clearly demonstrated by the Indian and Thai experiences. While in many other countries the initial reaction was 'What can modest savings achieve?', those who went along with the strategy found it empowered communities. Yves Cabanne, who works with cities and NGOs in Latin America, said after meeting with SDI groups and observing savings schemes in South Africa, he had initiated many similar schemes in Latin America.

The Alliance experience has been that although most saving schemes begin with what's left over after daily expenditure and permitting modest loans for crisis situations, soon the scheme advances to cover bigger savings and loans.

And scaling of savings, it is seen, is best left to mentors from communities. Here, the NGO's role is to provide a good information system to help local federations make better decisions.



'थोड़ी बचत से क्या हो सकता है?' से 'थोड़ी बचत से क्या नहीं हो सकता!' तक

समुदाय नेताओं, गैर सरकारी संस्थाओं के वित्त मैनेजर, द्विपक्षीय संस्थाओं से लोग और ऐशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के नागरी प्रतिनिधियों के 26 से अधिक समूहों ने मिल कर सामुदायिक धनराशी का प्रबन्धन करने के अलग अलग तरीकों पर वार्ता की। 11 और 14 जून की इन मीटिंगों के मेजबान थे ऐशियन कोअलिशन ऑफ हाउसिंग राइट्स, बैंकॉक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट, लंदन।

दैनिक बचत और मजबूत समुदाय प्रक्रियाओं का संबंध भारतीय और थाई अनुभवों ने स्पष्ट दिखाया। हालांकि कई दूसरे देशों में शुरु की भावना थी, 'थोड़ी सी बचत से क्या हो सकता है?', जिन्होंने भी इस तरीके को अपनाया उन्होंने पाया कि इससे समुदाय समर्थ हो गये हैं। लेकिन अमेरिका के शहरों और एन.जी.ओ. के साथ काम करने वाले इव्स कबान ने कहा की एस. डी.आई गुटों से मिल कर और दक्षिण अफ्रीका में बचत योजनायें देखने के बाद उन्होंने लैटिन अमेरिका में कई मिलती जुलती योजनायें चालू की हैं।

गठबंधन का अनुभव रहा है कि हालांकि अधिकतर बचत योजनायें रोज के खर्च के बाद रह गये पैसों से शुरु होती हैं जिससे तकलीफ के समय छोटे मोटे ऋण मिल जाते हैं, जल्द ही यह योजना बढ़ कर अधिक बचत और बड़े ऋण तक पहुंच जाती हैं। और यह भी देखा गया है, की बचत की बढ़ोतरी समुदायों के ही सलाहकारों पर छोड़ देनी चाहिये।

कोई भी शहर हो, दैनिक बचत और ऋण इकट्ठा करना और स्थानीय ऐरिया रिसोर्स सेंटर में उसे दर्ज करना घड़ी के जैसे चलता है। "यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था क्यों कि हमने वास्तव में देखा की संगठन कैसे चलता है", कहना था ए.बी.एन एमरो की मौमिता सेन शर्मा का जब वे भायखला, मुंबई के बचत चक्कर पर गयीं। उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने देखा की किस तरह सिर्फ आधे घंटे के अंदर, हर जमाकर्ता ने बस्ती का चक्कर पूरा किया, बचत और ऋण भुगतान इकट्ठे किये, ऋण के आवेदन नोट किये और वापस ऑफिस में आ कर हिसाब लिखवा दिया।



MUTP The Great North Mumbai Shift Begins

WARDWISE data of Mumbai shows that people are moving north in the wake of markets and business which are shifting northwards. Thousands of families who used to live in slums along the railway tracks also migrated northwards to permanent buildings when the Railways initiated the Mumbai Urban Transport Project (MUTP) to expand rail networks in the city. It was an enormous challenge for the Alliance to survey, resettle and thereafter support the thousands who - voluntarily - moved first into transit camps, (where they've lived for the last four years) prior to settling in permanent homes.

"Many of us came from different areas and so we didn't know each other. But living in this transit camp united us and we will continue to support each other when we move. We have formed eight housing societies with over a hundred families in each. And, over 70% of us have already saved the 20,000 rupees needed for the co-operative fund for increased maintenance costs after the move," said Gaekwad, an NSDF member from 138A transit camp in Mankhurd. Virtually all the 900 families from this area, plus another 1500 families from neighbouring transit camps of 138B and Turbe Mandala, have moved in April 2005 to their new buildings in Lallobhai Compound, situated within walking distance from where they live.

At resettlement time, the whole family gets to work. There's a festive air as everyone begins to pack their belongings and shifts to new homes in new locations.

पुनर्वसन के समय सारा परिवार काम में जुट जाता है। त्योहार का सा माहौल होता है जब सब अपना अपना सामान बांध कर नयी जगह पर नये घर में जाते हैं।

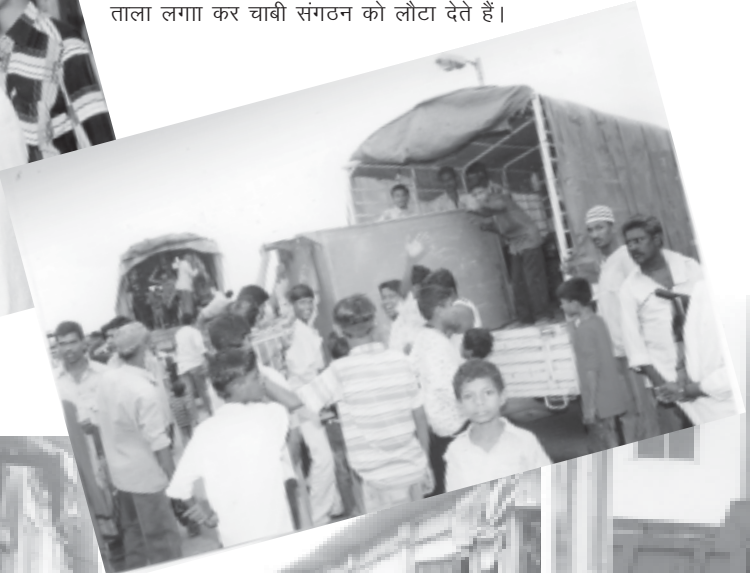
महान उत्तरी मुंबई प्रयाण शुरु हुआ

मुंबई के हर वार्ड के आंकड़े दिखा रहे हैं की जैसे जैसे बाजार और व्यापार उत्तर की ओर जा रहे हैं, लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब रेलवे ने शहर में रेल तंत्र बढ़ाने के लिये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एम.यू.टी.पी.) शुरु किया तो रेल लाइन के पास रहने वाले हजारों परिवार भी उत्तर में स्थित स्थायी इमारतों में चले गये। गठबंधन के लिये बहुत बड़ी चुनौती थी: उन हजारों के सर्वे करना, पुनर्वसन करना और बाद में स्थायी घरों में जाने से पहले उन हजारों परिवारों को सहारा देना जो स्वयं पहले ट्रांसिट कैम्प में आये और पिछले चार साल से वहां रह रहे हैं। "हम अधिकतर अलग अलग इलाकों से आये थे। इसलिये एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर इस ट्रांसिट कैम्प में रहने के बाद हम एक हो गये हैं और यहां से जाने के बाद भी एक दूसरे को सहारा देते रहेंगे। "हमने आठ गृह-संस्थाएं बनायी हैं और हर में सौ से अधिक परिवार हैं। और हम में से 70 प्रतिशत से अधिक ने अभी से रु. 20,000 बचा के रखे हैं उस सरकारी कोष के लिये जिससे नयी जगह में जाने के बाद बढ़े हुए मेन्टेनेंस का खर्चा निकलेगा, " यह कहना था गायकवाड का, जो मानखुर्द के 138 ए ट्रांसिट कैम्प में रह रहे एन.एस.डी. एफ. के सदस्य हैं। इस इलाके के सभी 900 परिवार, और पास के 138 बी और तुर्भे मंडाले के 2000 परिवार, अप्रैल 2005 में लल्लूभाई कम्पाउंड स्थित अपने नये घरों में चले गये हैं, जो कि अभी वाली जगह से पैदल दूरी पर ही है।



In transit camps, people from different areas get to know one another and bond. When it's time to leave, they lock up their homes and return the keys to the Federation.

ट्रांसिट कैम्पों में अलग अलग इलाके के लोगों की जान पहचान होती है और वे आपस में जुड़ते हैं। जब जाने का समय आता है, वे घरों पर ताला लगा कर चाबी संगठन को लौटा देते हैं।





एकता से हम चले

बड़े पुनर्वसन कोई बहुत सरल काम नहीं हैं। रोज की रोज नेता वार्ता करते हैं, और काम में देशी और जटिलताओं से निपटते हैं। पर सच्चाई यह है कि क्योंकि यह स्थानांतरण समुदाय-चलित हैं, इसलिये समस्याओं का समाधान सर्वसम्मति से जहां की तहां हो जाता है।

और तो और, चाहे पुनर्वसन स्वेच्छा से हुआ हो, मिल कर समस्याओं का समाधान करने से पुनर्वसन के परिणामस्वरूप होने वाले अवश्यम्भावी तनावों से निपटने में पूरा गुप सक्षम हो जाता है। संगठन-चलित प्रक्रिया में यही विशेष बात है। यह निर्णय लेने की ताकत गरीब के हाथ में देती है, फिर उन्हें अपने आप आगे बढ़ने का प्रशिक्षण दे कर सहारा भी देती है। इसी लिये संगठन समुदायों को प्रोत्साहित करता है की स्थानान्तरण के पहले प्रत्येक व्यक्ति रु. 25,000 की बचत करे। इससे जब वह अनौपचारिक से औपचारिक घरों में जाते हैं तो बड़े हुए रखरखाव के खर्चे चलाने में मदद मिलती है।

अधिक कमजोर गुटों को संगठन छोटे ऋण देता है; साथ ही वो अकेली मांओं और विधवाओं को -राशन की दुकानें चलाने या बिल्डिंग की देखरेख करने के काम देता है। यह सब करना जरूरी है जिससे लोग पुनर्वसन से मिलने वाले अच्छे घरों का लाभ उठा सकें।

यदि गरीबों को आर्थिक और सामाजिक सहारा नहीं होगा तो वे इस नयी जगह को संभाल नहीं पायेंगे और अपनी संपत्ति गवां देंगे।

MANAGING large relocations is, of course, no easy task. Community federations negotiate, sort out delays and complications on a daily basis. But the fact that the move is community-led means problems get sorted out on the spot and by consensus.

What's more, handling problems collectively strengthens the group's ability to deal with the inevitable strains resulting from re-location - even when it's voluntary. That's what is special about the federation-driven process: it places decision making in the hands of the poor, then trains and supports them to proceed on their own.

The Federation encourages communities to save Rs. 20,000 each before they shift. This helps them cover the rise in maintenance costs when they shift from

informal to formal housing.

For more vulnerable groups, the Federation gives small loans; it employs single mothers and widows in running ration shops or to service the buildings.

All this is necessary so that people may benefit from the better housing

that resettlement brings. If the poor are not financially and socially supported, they will be unable to afford the move and will lose their assets.

When the families arrive at the relocation sites, they are met by Federation leaders who formally register their names and give them the keys for their new homes. When the move is community led, problems get sorted out on the spot and by consensus.

जब परिवार पुनर्वसन की जगह पर आते हैं, संगठन के नेता उनसे मिलते हैं और औपचारिक रूप से उनके नाम दर्ज कर के उन्हें नये घर की चाबी देते हैं। जब परिवर्तन समुदाय प्ररित होता है तो समस्याओं का समाधान हाथों हाथ सर्वसम्मति से हो जाता है।





Moving Up

IN KANJUR MARG Transit Camp, the arrangement is slightly different. Families that live here will be resettled in multi-storeyed permanent accommodation on the same site. At the moment eight buildings, which will house about half the members, are almost ready. Once this shift occurs, the transit houses will be demolished and the remaining eight buildings put up. "Everyone is really keen to be in the first group to move, so we will work hard to create a system that's fair to everyone," said Mahila Milan leader 'Shetty Aunty' (as she is popularly known).

In fact, Kanjur Marg was the first transit camp under MUTP – an open marshy ground that was given to the Federation to resettle the first 800 odd families. "Eighteen men and women would come here everyday to level the ground, lay the water pipes and build the houses. At that time, many people in our area didn't believe we would ever leave the railway tracks. Once they moved here, they again said pessimistically, 'we'll never live in buildings'. Now they do not open their mouths to grumble because our buildings are coming up before our very eyes!"

Although most buildings on this site are being constructed by a private builder hired by MMRDA, the Alliance is constructing two buildings for 112 families under the Mumbai Urban Transport Project II.

Shopkeepers Complain to WB Inspection Panel

ONE hundred and eight shopkeepers along the Santa Cruz-Chembur Link Road, affected by the MUTP, complained to the Inspection Panel of the World Bank that the Bank's procedures were not followed in case of their proposed resettlement.

Their objection was that their business would be affected at the proposed relocation site in Mankhurd and they would get only 225 sq. ft. as opposed to their current larger spaces. The Chairperson of the Panel who visited Mumbai in 2004, returned in 2005 with other members to investigate the complaint.

Both MMRDA and SPARC/NSDF, in their presentations to the Panel, emphasized that these shopkeepers were neither poor nor slum dwellers. They felt such a small group out of 3,000 affected families should not be able to hold the project and the city to ransom. While negotiations with the shopkeepers continue, shifting of the families affected by the SCLR began in April 2005.

ऊंचाई की ओर

कांजुर मार्ग के अस्थायी कैम्प में व्यवस्था जरा हट कर है। उन्हें इसी जगह बन रही स्थायी बहुमंजिली इमारतों में पुनर्वसित किया जायेगा। अभी आठ इमारतें निर्माणाधीन हैं। इनमें लगभग आधे सदस्य आ जायेंगे। जब ये लोग हट जायेंगे तो अस्थायी घर तोड़ दिये जायेंगे और बाकी की 8 इमारतें बना दी जायेंगी। "सभी की बहुत इच्छा है कि वे पहले नये घरों में जायें, इसलिये हमे बहुत मेहनत से ऐसा तरीका बनाना होगा जो सब को उचित लगे।" महिला मिलन नेता शेट्टी आंटी (उनका लोक प्रिय नाम) ने कहा।

वास्तव में एम.यू.टी.पी. की तहत कांजुर मार्ग पहला ट्रांसिट कैम्प था। पहले आठसौ परिवारों को पुनर्वसित करने के लिये संगठन को दी गयी एक खुली दल दल जैसी जमीन। "आठ पुरुष और महिलाएँ रोज यहाँ आते थे जमीन समतल करने, पानी के पाइप डालने और घर बांधने। उस समय तो हमारे इलाके के कई लोगों को विश्वास भी नहीं था की हम रेलवे लाइन छोड़ कर जायेंगे। एक बार यहाँ आने के बाद भी उन्होंने निराशा से कहा था, 'हम बिल्डिंग में भी नहीं रहेंगे।' अब वो बड़-बड़ करने के लिये मूंह नहीं खोलते क्यों कि हमारी बिल्डिंगें हमारी आंखों के सामने खड़ी हो रही हैं।

"हालांकी इस जगह की ज्यादातर बिल्डिंगें एम.एम.आर.डी.ए. द्वारा नियुक्त निजी बिल्डर बना रहा है, गठबंधन 112 परिवारों के लिये दो बिल्डिंगों का निर्माण कर रहा है। यह सब जरूरी है जिससे कि लोगों को पुनर्वसन से मिलने वाले अच्छे घरों का लाभ मिल सके।



World Bank and MMRDA teams regularly visit families at resettlement sites to discuss their experiences.

वर्ल्ड बैंक और एम.एम.आर.डी.ए. के दल नियमित रूप से पुनर्वसन जगहों पर परिवारों से मिलने व उनके अनुभव सुनने जाते हैं।

दुकानदारों ने की बैंक निरीक्षकों से शिकायत

सांताक्रुज – चेंबूर लिंक रोड पर एम.यू.टी.पी. से प्रभावित 108 दुकानदारों के गुट ने वर्ल्ड बैंक के निरीक्षण दल – एक स्वतंत्र निगम जो बैंक के विरुद्ध शिकायतें सुनता है – से शिकायत की कि उनके प्रस्तावित पुनर्वसन में बैंक की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

उन्हें मानखुर्द स्थित प्रस्तावित पुनर्वसन जगह पर आपत्ति थी क्यों कि इससे उनके धंधे पर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें अपनी बड़ी दुकान के बदले में सिर्फ 225 वर्ग फुट जगह मिलेगी। निरीक्षण दल के अध्यक्ष एवं सचिव 2004 में मुंबई यह देखने आये की शिकायत पर विचार किया जाये या नहीं और 2005 में इसकी जांच पड़ताल करने वे बाकी सदस्यों को ले कर आये। दल के समक्ष प्रस्तुतिकरण में एम.एम.आर.डी.ए. और स्पार्क/एन.एस.डी.एफ. ने जोर दिया की ये दुकानदार न तो गरीब हैं न ही झोंपड़पट्टीवासी। यह भी दिखाया गया की एस.सी.एल.आर. से प्रभावित लगभग 3000 परिवारों में से इतना छोटा सा गुट परियोजना और शहर को बंधक नहीं रख सकता।

दुकानदारों से बातचीत चालू है इसी बीच –एस.सी.एल.आर. प्रभावित परिवार अप्रैल 2005 से पुनर्वसन के लिये नयी जगह जाना शुरू करेंगे।



वाशी नाका के कठिन विकल्प

अगस्त और दिसम्बर 2004 के बीच कोकरी आगार ट्रांसिट कॅम्प के लगभग 3000 परिवार वाशी नाका स्थित नये घरों में गये। क्षेत्र में काम कर रहे सभी एन.एस.डी.एफ. और महिला मिलन नेताओं के लिये यह बहुत मेहनत का समय था। उन्हें जांच करनी थी कि हर परिवार किसी सहकारी संस्था में है या नहीं, उसे इमारत, मंजिल, कमरा नम्बर मिला है या नहीं और सारे कागजात सही हैं या नहीं। बिल्डिंगों में एक ऑफिस बनाया गया जिससे प्रक्रिया सुविधापूर्वक हो सके पर वाशी नाका जाने वाला रास्ता अटकलों से भरा था। जब वर्ल्ड बैंक ने रेलवे लाइन पर रहने वाले परिवारों के लिये ट्रांसिट घरों की मंजूरी दी थी तो इस शर्त पर की तीन साल के अंदर ये परिवार वहां से हट जायेंगे। यह अविधि 2004 में पूरी हो चुकी थी। राज्य और समुदाय दोनों ही जाने की तैयार थे, 2004 तक कई घर तैयार भी थे लेकिन आवश्यक संसाधन अभी नहीं मिले थे। साथ ही एन.एस.डी.एफ. पर समुदाय और सरकार दानों ही से दबाव आ रहा था कि लोगों को स्थायी घरों में भेजे। एन.एस.डी.एफ. के सामने बड़ा कठिन चुनाव था—क्या वो जाने में देरी करे और राह देखे की एम.एम.आर. डी.ए. (महाराष्ट्र मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथोरिटी) पानी के कनेक्शन चालू कर दे या फिर वो स्थानांतरण से पैदा हुए उत्साह और शक्ति के चलते थोड़े समय पानी खरीद ले और बाद में पैसा ले ले। संगठन ने दूसरा उपाय चुना। एम.एम.आर.डी.ए. हर परिवार को नयी जगह जाने के लिये गाड़ी का किराया रु.300 देती है। गति बनाये रखने के लिये एन.एस.डी.एफ. सदस्यों ने यह राशि परिवारों को पहले से ही दे दी कि यह भी बाद में ले लेंगे। एक और समस्या थी की जाने के समय स्कूल चालू थे और बच्चों को कोकरी आगार स्थित स्कूलों तक पहुंचाने के लिये कोई बसें उपलब्ध नहीं थीं। एन.एस.डी.एफ. ने बच्चों के लिये दो बसों का इंतजाम किया जिससे की स्कूल चालू रहने तक बच्चों को तकलीफ न हो। इस का भुगतान भी एम.एम.आर.डी.ए. करेगा। कहने का मतलब है कि पुनर्वसन बहुत जटिल होता है और जाने की परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होतीं और यदि हर मौके का फायदा नहीं उठाया जाये तो फायदे हाथ से निकलने का डर भी रहता है। इसलिये जोखिम कम करने के लिये गठबंधन बीच में पड़ता है और पानी, वाहन और स्कूली बच्चों के लिये बस का इंतजाम जैसी समस्याएँ अपने ऊपर लेता है।



NSDF organised buses to Kokari Agar for schoolgoing kids as relocation to Vashi took place in the middle of the academic year.

एन.एस.डी.एफ. ने स्कूली बच्चों के लिये कोकरी आगार तक बसों का इंतजाम किया क्यों की वाशी पुनर्वसन के समय स्कूल चालू थे।

Tough Choices at Vashi Naka

NEARLY 3,000 families from Kokari Agar Transit Camp moved into new apartments at Vashi Naka between August and December, 2004.

With communities self-selecting co-op members and neighbours, the role of the NSDF and Mahila Milan leadership is to make sure no one is left out. An office was set up in the new buildings to further facilitate the process.

The relocation to Vashi Naka had its own set of problems. When the World Bank agreed to explore transit accommodation for households along the railway track, a caveat was included to ensure that households were moved within three years – which period ended in 2004.

Both the State and the communities were keen on the move. But while many apartments were ready by 2004, all the necessary infrastructure was not in place. At the same time, NSDF was under pressure from both communities and government to make the move.

NSDF was faced with a tough choice: should it delay the shifting and wait for the MMRDA (Maharashtra Metropolitan Region Development Authority) to lay the water connections? Or should it harness the energy and excitement created by the shift, pay for water in the interim, and get reimbursed later? The Federation chose the second option.

Yet another problem was that the shift happened in the middle of the school year and there were no bus services to take children to their schools in Kokari Agar. NSDF organised two buses for all the kids so that they were not inconvenienced until the end of the school year, the amount to be charged to MMRDA.

The point is that resettlement is always complex and conditions for a move, never ideal. And if every opportunity is not capitalised on, there is always the danger of losing benefits. So the Alliance steps in to mitigate the risk and streamline the shift, taking upon itself tasks such as providing water, transport, and busing for schoolgoing children.



Partnering with the AP Housing Board

"I HAVE now got an office in the State housing authority's building!" laughs Ramesh, member of the Andhra Pradesh Slum Dwellers Federation (APSDF). He has just finished coordinating a detailed survey of 350 families living in three slums across the city of Hyderabad. APSDF will, in consultation with the families, assist in relocating them to multi-storey houses built by the AP Housing Board (APHB).

The story of why Ramesh now sits along with other members of his federation in the APHB office begins in February 2005, when APHB approached the Alliance with a very interesting proposition – to help convince the 350 families that they should move. Rather than evict or force relocation, the APHB wanted to seek a middle path so that they got their valuable land and people got a housing option of their choice. APSDF therefore surveyed the households, briefed them on the project and began looking at affordable housing options.

A month later, the Housing Board came back with yet another project. They planned to build one lakh houses for low income groups and wanted help to identify these groups, verify their eligibility, organize them into co-ops and set up repayment systems. They also wanted help in mentoring other NGOs to take up similar work. To take on such a large scale housing project in the city was, of course, a tremendous opportunity...

For the Alliance, this partnership with the State is an important acknowledgement by the authorities that they need to collaborate with organised communities to effectively implement pro-poor projects. Much of this recognition springs from the fact that for the last year the Federation has been working on sanitation in various cities of AP. The first 40-seat community toilet has been completed in Hyderabad, the Alliance has built 14 toilet blocks in Vijaywada, and has just taken up a citywide sanitation programme in Vizag. Watching these successes, other city authorities are keen to work with the Alliance on their projects.



आंध्र प्रदेश आवास निगम के साथ भागीदारी

"मेरे पास अब राज्य आवास निगम की बिल्डिंग में ऑफिस है!", आंध्र प्रदेश झोंपड़पट्टीवासी संगठन ए.पी.एस.डी.एफ. के सदस्य रमेश ने हंस के बताया। उसने हैदराबाद की तीन झोंपड़पट्टियों में रह रहे 350 परिवारों के विस्तृत सर्वे का समन्वय किया है। ए.पी.एस.डी.एफ. इन परिवारों से परामर्श कर उन्हें ए.पी. आवास निगम द्वारा निर्मित बहुमंजिली इमारतों में पुनर्वसन के लिये मदद करेगा। रमेश अपने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ ए.पी.एस.बी ऑफिस में क्यों बैठता है? यह कहानी शुरु हुई फरवरी 2005 में जब ए.पी.एस.बी. गठबंधन के पास बड़ा ही रोचक प्रस्ताव ले कर आये। उन्हें सहायता चाहिये थी, लगभग 400 परिवारों को मनाने की जिससे वे कुछ सार्वजनिक निर्माण काम चालू कर सके। इसलिये ए.पी.एस.डी.एफ. ने परिवारों का सर्वे किया, उन्हें परियोजना के बारे में बताया और उचित घरों की तलाश शुरु की।

एक महीने बाद आवास निगम एक और परियोजना ले कर आया। उन्होंने कम आय वर्ग के लिये एक लाख घर बनाये थे और अब वे मदद चाहते थे इस वर्ग को पहचानने में, उनकी योग्यता निश्चित करने में और उन्हें पुनर्वसित करने में; साथ ही ऐसे काम करने के लिये अन्य गैर सरकारी संगठनों को प्रेरित करने में। शहर में इतने बड़े स्तर की आवास योजना में काम करना तो बहुत बड़ा अवसर था ही.....

गठबंधन के लिये राज्य के साथ यह भागीदारी एक स्वीकृति थी की यदि वे प्रभावी रूप से गरीबों के हित में पुनर्वसन योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते हैं तो सत्ता को संगठित समुदायों के साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है। काफी मान्यता तो इसलिये भी मिली क्यों कि पिछले एक साल से गठबंधन आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों में शौचालयों पर काम कर रहा है। पहला 40 सीट का समुदाय शौचालय हैदराबाद में पूरा हो चुका है। गठबंधन ने विजयवाड़ा में 14 शौचालय संकुल बनाये हैं और जल्द ही वाइजैग में शौचालय कार्यक्रम शुरु करने वाला है। इन सफलताओं को देखते हुए शहर के अन्य अधिकारी भी अपनी अपनी परियोजनाओं में गठबंधन के साथ काम करने के इच्छुक हैं।



AP Housing Board takes the middle path: persuades 350 Hyderabad families to relocate voluntarily to affordable housing.

आंध्र प्रदेश आवास निगम ने मध्य मार्ग अपनाया : उसने 350 हैदराबादी परिवारों को स्वयं कम कीमत के घरों में जाने के लिये समझाया।